वर्ष 12 • अंक 296 • 16 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 31 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

दिसंबर तिमाही में सोने की घटी मांग

एलन जोप ▶▶ पृष्ठ 2

यूनिलीवर करेगी चाय कारोबार की समीक्षा

डॉलर रु. 71.50 ▲ 20 पैसे | यूरो रु. 78.80 ▲ 40 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40684 ▲ 382 रुपये | सेंसेक्स 40913.80 ▼ 284.80 | निफ्टी 12035.80 ▼ 93.70 | निफ्टी फ्यूचर्स 12059.90 ▲ 24.10 | ब्रेंट क्रूड 57.30 डॉलर ▼ 1.50 डॉलर

बजट अंक

रविवार 2 फरवरी के अंक में पढ़िए आम बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकली सौगात और कहां लगाई घात। आम लोगों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की बात। आम बजट का संपूर्ण विवरण।

एक नज़र

बजट सत्र आज से शुरू 1 फरवरी को आम बजट

संसद का बजट सत्र शुक्रवार को शुरू होगा और शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। शुक्रवार को ही आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। संशोधित नागरिकता कानून समेत सरकार के नागरिकता संबंधी किए गए उन सभी उपायों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध के बीच इस सत्र का आयोजन हो रहा है, जिनको लेकर विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोले हुए हैं।

टाटा मोटर्स का कर पूर्व लाभ 1,350 करोड़ रुपये

दिसंबर तिमाही में टाटा मोटर्स ने एकीकृत आधार पर लाभ दर्ज किया। जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की मालिक को लगातार छठे महीने चीन में बिक्री बढ़ने से फायदा मिला। कंपनी की आय को बेहतर बिक्री के अलावा परियोजना लागत में बचत से भी मजबूती मिली। दिसंबर तिमाही में कंपनी का कर पूर्व लाभ 1,350 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में उसे 29,228 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान हुआ था। इस अवधि में एकीकृत स्तर पर शुद्ध लाभ 1,755.88 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में उसे 26,960.8 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ था। कंपनी का कुल परिचालन राजस्व 71,676.07 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 76,915.94 करोड़ रुपये रहा। पृष्ठ 3

सरकारी बैंकों में शुक्रवार से दो दिन की हड़ताल

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी शुक्रवार से दो दिन की हड़ताल पर रहेंगे। इससे सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। वेतन संशोधन को लेकर प्रबंधन के साथ बातचीत में सहमति नहीं बनने के बाद बैंक यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि हड़ताल से उनका सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रभावित हो सकता है। सरकारी बैंकों की हड़ताल ऐसे समय हो रही है जब शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया जाना है।

मोबाइल निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क प्रोत्साहन

सरकार ने मोबाइल फोन निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से दो फीसदी का अतिरिक्त शुल्क प्रोत्साहन को बहाल कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भारत से वस्तुओं के निर्यात की योजना के तहत शुल्क लाभ एक जनवरी से 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त अस्थायी प्रोत्साहन को अधिसूचित किया गया है। यह सुविधा 1 जनवरी से 31 मार्च, 2020 तक के लिए है।

त्यापार गोष्ठी

कोरोना वायरस जैसे संकट से कैसे बचें?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या कर संग्रह में कमी का बजट में दिखेगा असर

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या टाटा एयर इंडिया के लिए बोली लगाने में होगी सक्षम?	हां	65.38%
	नहीं	34.62%

कर लक्ष्य में सबसे बड़ी कटौती!

आम बजट में वित्त मंत्री कर सकती हैं मौजूदा कर लक्ष्य में कमी की घोषणा

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 30 जनवरी

आर्थिक मंदी और कंपनी कर में कटौती की वजह से सरकार को आगामी बजट में 2019-20 के कर राजस्व अनुमानों में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये के बीच कटौती करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में यह अनुमानित राजस्व से वास्तविक वसूली के बीच सबसे बड़ा अंतर होगा। पिछले साल फरवरी के अंतरिम बजट में 25.5 लाख करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, जो इसके पहले साल के वास्तविक कर संग्रह की तुलना में 22.5 प्रतिशत ज्यादा है। यह तीसरा मौका होगा जब वित्त वर्ष 19 के कर अनुमान में बदलाव किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर के 5 फीसदी रहने का अनुमान है जो 11 साल में सबसे कम है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में मांग कम है, ऐसे में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह भी प्रभावित हुआ है। प्रत्यक्ष कर संग्रह 15 दिसंबर तक महज 0.7 प्रतिशत बढ़ा है। बहरहाल अप्रत्यक्ष कर छूट योजना सबका विश्वास (उत्तराधिकार विवाद समाधान योजना) ने इज्जत बचा ली है और इसके जरिये सरकार के खजाने में अतिरिक्त 38,000 करोड़ रुपये आए हैं।

- 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकती है कटौती
- आर्थिक मंदी और कंपनी कर में कटौती से कम रह सकता है संग्रह
- प्रत्यक्ष कर संग्रह 15 दिसंबर तक महज 0.7 प्रतिशत बढ़ा

सरकार के राजस्व लक्ष्य के अनुमानों पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सवाल उठाया है। उसका कहना है कि आर्थिक मंदी के बावजूद इस वित्त वर्ष में उच्च वृद्धि का अनुमान संदेह पैदा करता है। जुलाई में जब पूर्ण बजट पेश किया गया तो कर संग्रह का अनुमान 90,000 करोड़ रुपये कम कर दिया गया, लेकिन इसमें भी 18.26 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान रखा गया, जो 2018-19 में हासिल 8.3 प्रतिशत वृद्धि से बहुत ज्यादा है।

वित्त वर्ष 2018-19 में 1.67 लाख करोड़ रुपये की भारी कमी आई थी, जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा गिरावट थी और वित्त वर्ष 15 के बाद पहली बार पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व के अनुमान में कटौती की गई थी, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।

केयर रेटिंग में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'आदर्श रूप में वित्त वर्ष के लिए कर संग्रह में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये की कटौती आगामी बजट में होनी चाहिए।' नोटबंदी का साल 2016-17 एकमात्र ऐसा साल था, जब वास्तविक कर संग्रह 17.1 लाख करोड़ रुपये था और यह 16.3 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 17 लाख करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमान को पार कर गया था। बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि 2016-17 और 2017-18 को अलग करके रखा जाना चाहिए और 2018-19 और 2019-20 जैसे सामान्य वर्षों के हिसाब से लक्ष्य तय किए जाने चाहिए।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'नोटबंदी के साल देखे गए संग्रह के रुझानों के जारी रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए वृद्धि के अनुमान लगाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तब नए करदाता जुड़े थे और लोगों ने अपने आय कर रिटर्न को संशोधित किया था।'

वित्त वर्ष 2019 में कर विभाग ने बजट अनुमानों में संग्रह लक्ष्य को 11.5 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 11.3 लाख करोड़ रुपये करने की पैरवी की थी लेकिन इसके बजाय उसे किसान से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च 50 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वसूलने का जिम्मा दिया गया था।

संशोधित संग्रह लक्ष्य में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 9 फीसदी की गिरावट के साथ 4.5 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि वित्त वर्ष के दौरान कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती के कारण इसमें गिरावट आई।

कोटक के प्रवर्तक रख पाएंगे 26 फीसदी हिस्सा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 30 जनवरी

उदय कोटक
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

- आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को दी नियम से राहत
- बैंक प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी घटाकर वोटिंग इक्विटी शेयर के 26 फीसदी तक लानी होगी
- आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक ने बंबई उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक को प्रवर्तकों की हिस्सेदारी घटाकर 26 फीसदी पर लाने और उनके मताधिकार को सीमित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

आरबीआई ने गत 29 जनवरी को भेजे एक पत्र में इस फैसले की जानकारी दी है। इसके मुताबिक आरबीआई की अंतिम अनुमति मिलने के छह महीनों के भीतर बैंक के प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी घटाकर वोटिंग इक्विटी शेयर के 26 फीसदी तक ले आनी होगी।

आरबीआई नियमों के मुताबिक, कोटक महिंद्रा बैंक को अपने प्रवर्तकों की हिस्सेदारी को 31 दिसंबर 2018 तक घटाकर 20 फीसदी और मार्च 2020 तक 15 फीसदी पर ले आना अनिवार्य था। लेकिन आरबीआई ने अब कोटक महिंद्रा को इस नियम में ढील दे दी है।

कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी उदय कोटक की अगुआई वाले प्रवर्तकों के पास दिसंबर 2019 में शेयर पूंजी के 29.96 फीसदी का स्वामित्व था। लेकिन आरबीआई की इस मंजूरी के बाद प्रवर्तकों के मताधिकार की सीमा कम हो जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक प्रवर्तकों के पास वोटिंग इक्विटी शेयर का 20 फीसदी रहेगा और 1 अप्रैल, 2022 तक इसमें और कमी करते हुए 15 फीसदी कर दिया जाएगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि शेयरधारिता में कटौती के बाद प्रवर्तक उस समय तक बैंक का कोई और वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं खरीद पाएंगे जब तक कि उनकी हिस्सेदारी 15 फीसदी या भविष्य में आरबीआई द्वारा तय की जाने वाली सीमा तक नहीं आ जाती है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि प्रवर्तकों को अतिरिक्त शेयर खरीद कर बैंक की 15 फीसदी इक्विटी पूंजी जुटाने की अनुमति होगी। खास बात यह है कि प्रवर्तकों को इन शेयरों पर मताधिकार भी होगा। रिजर्व बैंक इस सीमा में भविष्य में बदलाव भी कर सकता है।

बैंक ने आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद बंबई उच्च न्यायालय में दायर अपनी रिट याचिका वापस ले ली है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी दी है। दिसंबर 2018 में बैंक ने उच्च न्यायालय में आरबीआई के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका उस समय दायर की गई थी जब आरबीआई ने तरजीही शेयर जारी कर प्रवर्तकों की शेयरधारिता में कमी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था।

कोटक महिंद्रा ने अगस्त 2018 में परपेचुअल गैर-परिवर्तनीय तरजीही शेयर जारी किए थे। बैंक ने कहा था कि इससे प्रवर्तकों की शेयरधारिता 30.3 फीसदी से घटकर 19.7 फीसदी हो जाएगी लेकिन बैंकिंग नियामक उसके सुझाए गए तरीके से सहमत नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के इस बैंक ने आरबीआई के निर्देश से अंतरिम राहत देने की मांग अपनी याचिका में की थी। (शेष पृष्ठ 3 पर)

वायरस से बढ़ी चिकित्सा उपकरणों की मांग

सोहिनी दास
मुंबई, 30 जनवरी

- मास्क जैसे चिकित्सा उपकरणों की मांग में अचानक बढ़ोतरी
- घरेलू बाजार के साथ-साथ चीन सहित निर्यात बाजारों में मांग में तेजी
- मास्क जैसे अहम उत्पादों की कीमत 60 फीसदी तक बढ़ी

स्वास्थ्य सेवा उद्योग खासकर अस्पतालों में एक बार इस्तेमाल होने वाला सामान बनाने वाली बेंगलूरु की कंपनी डिस्पोलीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास मास्क के बारे में पूछताछ के मामले 15 गुना बढ़ गए हैं और बिक्री भी चार से पांच गुना बढ़ी है। दुनिया के कई देशों में कोरोनावायरस के मामले सामने आए हैं और इससे बचाव के लिए पहने जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की मांग बढ़ गई है। इतना ही नहीं चीन से आपूर्ति बाधित होने से चिकित्सा उपकरण बनाने वाली भारतीय कंपनियों को सुनहरा मौका मिला है। इससे न केवल घरेलू मांग बढ़ी है बल्कि निर्यात बाजारों से भी ऑर्डर बढ़े हैं।

डिस्पोलीन इंडिया खुद मास्क नहीं बनाती है बल्कि ठेके पर इन्हें बनवाती है। कंपनी के मालिक सुमित मड़वा ने कहा कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि देश में मास्क का बाजार कितना बड़ा है लेकिन इनकी संख्या अरबों में है। आजकल खासतौर पर एंटी-वायरल मास्क की मांग में बढ़ोतरी हुई है। ये एन-95 मास्क हैं। मड़वा ने कहा कि नियमित मास्क की न्यूनतम एक्स-फैक्टरी कीमत एक रुपये है। चीन से भी एन-95 मास्क के बारे में पूछताछ की जा रही है और वहां की कंपनियां भारत से इसके आयात की संभावनाएं तलाश रही हैं। इसकी कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां एक मास्क 20 से 25 रुपये में मिलता था, अब उसकी कीमत करीब 40 रुपये पहुंच गई है।

चिकित्सा उपकरण बनाने वाले मुंबई के एक निर्माता ने कहा, 'व्यापारी निर्माताओं से मास्क खरीद रहे हैं और उनका विदेश निर्यात किया जा रहा है। खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से मांग में काफी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ी हैं। इतना ही नहीं सरकार भी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बड़े पैमाने पर मास्क खरीद रही है।'

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डेवाइसेज (एआईएमईडी) के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा कि चीन के कई प्रांतों में कोरोनावायरस का प्रकोप फैलने से चिकित्सा उपकरणों की मांग आई है। भारत में 80 फीसदी चिकित्सा उपकरणों का अमेरिका, यूरोप और चीन से आयात किया जाता है। इसमें चीन की भागीदारी करीब 10 फीसदी है।

कोरोनावायरस का पहला मामला केरल में

देश में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में सामने आया है। चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही एक छात्रा में कोरोनावायरस की पुष्टि हुई है और उसे अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है। पीआईबी के मुताबिक मरीज की हालत स्थिर है और उसके स्वास्थ्य पर करीबी नजर रखी जा रही है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। पृष्ठ 16

कारोबार पर भी कोरोना का असर

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जनवरी

- चीन से आयात ऑर्डर टाल रहे दिल्ली के थोक कारोबारी
- चीन के प्रमुख थोक बाजार ईवू से होता है मुख्य तौर पर आयात
- उड़ानें रद्द होने से भारतीय एजेंटों के चीन जाने पर संकट

चीन में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस का असर पुरानी दिल्ली के बाजारों पर पड़ सकता है। चीन के बाजारों में छुट्टियां बढ़ाने की खबरें आ रहे हैं और भारत सरकार ने भी चीन जाने वाली कुछ उड़ान रद्द कर दी हैं। अगर लंबे समय तक हालात ऐसे ही रहे तो चीन और पुरानी दिल्ली के कारोबारियों के बीच होने वाले कारोबार पर बड़ी मार पड़ सकती है। चीन का ईवू बड़ा थोक बाजार है और वहां से पुरानी दिल्ली के कारोबारी भी बड़ी मात्रा में माल मंगाते हैं। अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 4 लाख भारतीय कारोबारी ईवू जाते हैं।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष और चीन से गैस चूल्हा कलपुर्जे आयात करने वाले देवराज बवेजा कहते हैं, 'चीन में छुट्टियां खत्म होने का समय नजदीक आने के कारण अब ऑर्डर देने की तैयारी चल रही थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण भारत से चीन जाने वाली उड़ानें रद्द होने से फिलहाल ऑर्डर टाल दिए गए हैं।' उड़ानें रद्द होने के कारण भारतीय कारोबारियों के एजेंट चीन नहीं जा सकेंगे, जो छुट्टियों के कारण भारत आए हुए हैं। होली पर चीनी पिचकारी की आपूर्ति प्रभावित होने के सवाल पर बवेजा ने कहा कि पिचकारी के ज्यादा ऑर्डर दिए जा चुके हैं और इनकी आपूर्ति या तो हो चुकी है या होने वाली हैं। ऐसे में इस कारोबार पर बड़े असर की संभावना नहीं है। एक अन्य पिचकारी कारोबारी ने कहा कि आपूर्ति पर भले असर न हो लेकिन खुदरा कारोबारी इसकी आड़ में दाम बढ़ा सकते हैं। भागीरथ प्लेस बाजार में लाइटिंग सामान आयातक अशोक मल्होत्रा ने कहा कि वायरस फैलने के बीच कोई भी कारोबारी ऑर्डर देने चीन नहीं जाना चाहेगा। इसलिए आयात के ऑर्डर बंद करना ही ठीक है। सदर बाजार के खिलौना कारोबारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी आपूर्ति पर असर नहीं हुआ है लेकिन ऐसे ही हालत रहे तो कारोबार प्रभावित हो सकता है।

कार्यकारी भूमिका से हटे राहुल बजाज

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 30 जनवरी

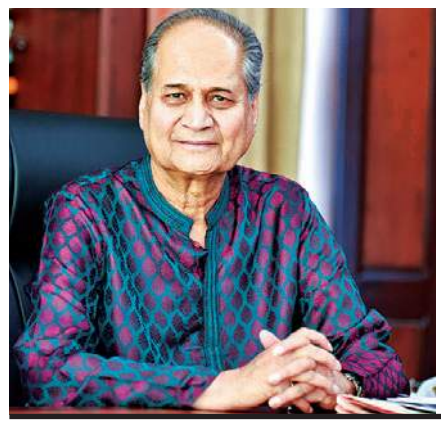

- बजाज होल्डिंग्स और बजाज ऑटो तथा बजाज फिनसर्व सहित सूचीबद्ध कंपनियों का चेयरमैन पद छोड़ेंगे राहुल बजाज
- कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी के लिए लाएगी विशेष प्रस्ताव
- 1 अप्रैल, 1970 से ही संभाल रहे थे चेयरमैन की जिम्मेदारी

कई दशकों तक बजाज समूह का चेहरा रहे राहुल बजाज ने ग्रुप में कार्यकारी भूमिका से हटने का फैसला किया है। उन्होंने समूह की होल्डिंग कंपनी बजाज होल्डिंग्स ऐंड इनवेस्टमेंट और बजाज ऑटो तथा बजाज फिनसर्व सहित सूचीबद्ध कंपनियों का चेयरमैन पद छोड़ने का निर्णय लिया है।

पल्सर ब्रांड की मोटरसाइकिल और आरई तिपहिया बनाने बनाने वाली बजाज ऑटो ने आज कहा कि राहुल बजाज अब गैर कार्यकारी भूमिका में नजर आएंगे। वह 1 अप्रैल, 1970 से कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और चेयरमैन थे।

वह बजाज ऑटो में सफल बदलाव के सूत्रधार थे। कभी यह कंपनी चेतक ब्रांड का लोकप्रिय स्कूटर बनाती थी लेकिन आज वह 70 से भी अधिक देशों में मोटरसाइकिल बेचती है। 2005 तक उन्होंने कंपनी में सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बाद समूह की कंपनियों की कमान अपने बेटों को सौंप दी। उन्होंने बड़े बेटे राजीव बजाज को वाहन कारोबार की जिम्मेदारी दी और छोटे बेटे संजीव बजाज को वित्तीय सेवा कारोबार की कमान सौंपी।

बजाज ने ऐसे समय समूह में शीर्ष पद से इस्तीफा दिया है जब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश की शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पद अलग करने का आदेश दिया है। बाजार नियामक का कहना है कि कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक होना चाहिए और उसका प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्याधिकारी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हालांकि इस आदेश के क्रियान्वयन को दो साल के लिए टाल दिया गया है। बजाज समूह ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा है कि राहुल बजाज का कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। कुछ प्रतिबद्धताओं और पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण उन्होंने अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नहीं बने रहने का फैसला किया है।

बजाज पहले ही 75 साल के हो चुके हैं। कंपनी इस बारे में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए एक विशेष प्रस्ताव लाएगी। बुधवार को समूह की वित्तीय सेवा कारोबार से जुड़ी कंपनी बजाज फिनसर्व और उसकी सहयोगी कंपनी बजाज फाइनैंस और बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस ने बजाज के इस्तीफे की जानकारी दी थी।

उदारीकरण के दौर से पहले अपनी बेबाकी और सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना के लिए जाने जाने वाले बजाज को पद्म भूषण से नवाजा गया है। वह हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल के छात्र रहे बजाज की पहचान कंपनी जगत में ऐसे शख्स की रही है जो बड़ी बेबाकी के साथ राष्ट्रीय हित या उद्योग जगत के मुद्दों को उठाता है। पिछले साल 30 नवंबर को इकनॉमिक टाइम्स द्वारा मुंबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राहुल बजाज ने कहा कि वह पैदाइशी सत्ता विरोधी हैं। 1970 के दशक में जब इटली की कंपनी पियाजियो ने बजाज के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया तो उन्होंने चेतक और सुपर ब्रांड से खुद ही स्कूटर बनाने शुरू कर दिए।

खबरों में रहे स्टॉक

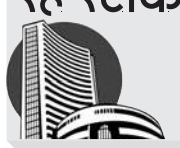

रिलायंस इंडस्ट्रीज

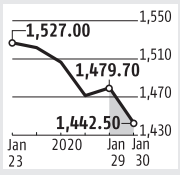

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 1,479.70 पिछला बंद भाव
₹ 1,442.50 आज का बंद भाव
▼ 2.51 %

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स

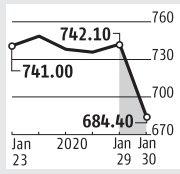

तीसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री महज 2 फीसदी बढ़ी

₹ 742.10 पिछला बंद भाव
₹ 684.40 आज का बंद भाव
▼ 7.78 %

एस्कॉर्ट्स

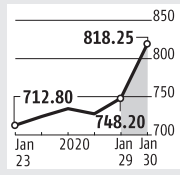

ट्रैक्टर बिक्री में सुधार की उम्मीद में चढ़ा शेयर

₹ 748.20 पिछला बंद भाव
₹ 818.25 आज का बंद भाव
▲ 9.36 %

कोलगेट-पामोलिव (इंडिया)

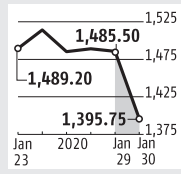

तीसरी तिमाही में मात्रात्मक बिक्री उम्मीद से कम बढ़ी

₹ 1,485.50 पिछला बंद भाव
₹ 1,395.75 आज का बंद भाव
▼ 6.04 %

अरबिंदो फार्मा

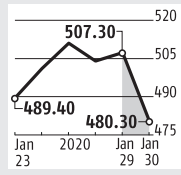

यूएसएफडीए ने यूनिट-7 के लिए जताई आपत्ति

₹ 507.30 पिछला बंद भाव
₹ 480.30 आज का बंद भाव
▼ 5.32 %

संक्षेप में

म्युचुअल फंडों के अभियान से जुड़े सचिन, धोनी

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने गुरुवार को कहा कि उसने दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को म्युचुअल फंड अभियान 'म्युचुअल फंड सही है' से जोड़ा है। यह अभियान वित्तीय उत्पादों को निवेश का तरजीही विकल्प बनाने के लिए जागरूकता पैदा करने के इरादे से चलाया जा रहा है। यह पहला मौका है जब उद्योग ने जागरूकता अभियान से सिलेब्रिटी को जोड़ा है, जिसे मार्च 2017 में पेश किया गया था। *एजेंसियां*

एनसीडी से 4,175 करोड़ रु. जुटाएगा ऐक्सिस बैंक

निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने निजी नियोजन के आधार पर गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) जारी कर 4,175 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। बैंक ने गुरुवार को कहा, बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों की समिति ने 10 लाख रुपये अंकित मूल्य के 41,750 विमोच्य गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने की मंजूरी दी है। इस निर्गम की ब्याज दर 7.65 फीसदी वार्षिक होगी। रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल और इक्रा ने इन ऋणपत्रों को एएए स्थिर रेटिंग दी है। *भाषा*

डाबर इंडिया का लाभ करीब 8 फीसदी बढ़ा

तेल, साबुन जैसे दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया लि. ने दिसंबर, 2019 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 398.87 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 8.62 फीसदी अधिक है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 367.21 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 6.99 फीसदी बढ़कर 2,352.97 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। *भाषा*

यूनिलीवर करेगी चाय की समीक्षा

कमजोर बिक्री के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर चाय कारोबार की समीक्षा करेगी कंपनी

रॉयटर्स
बेंगलूरु, 30 जनवरी

बहुराष्ट्रीय एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर ने बिक्री में कमजोर वृद्धि के मद्देनजर अपने वैश्विक चाय कारोबार की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसे कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी एलन जोप की स्पष्ट रणनीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जोप ने इससे पहले कहा था कि कंपनी ने लंबी अवधि के लिहाज से अपने चाय कारोबार में निवेश किया है लेकिन निवेशकों की चिंता के कारण संभवत: योजना में बदलाव किया गया है। निवेशकों ने यूनिलीवर के फूड ऐंड रीफ्रेशमेंट कारोबार की सुस्त रफ्तार को लेकर चिंता जताई थी।

यूनिलीवर के मुख्य वित्तीय अधिकारी ग्रैम पिकेथली ने गुरुवार को कंपनी के वित्तीय नतीजे जारी करने के बाद कहा, 'हम इस कारोबार (चाय) के लिए सभी विकल्पों पर गौर कर रहे हैं।' पिछली तिमाही के दौरान समूह की बिक्री में बढ़त की रफ्तार पिछले एक दशक में सबसे सुस्त दर्ज की गई।

पिकेथली ने कहा कि उभरते बाजारों और प्रीमियम श्रेणी में में चाय कारोबार का प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन सभी क्षेत्रों एवं इस कारोबार के सभी हिस्सों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने इसके लिए किसी समय-सीमा का खुलासा नहीं किया लेकिन कहा कि आंशिक अथवा पूरी बिक्री जैसे विकल्प मौजूद हैं।

कंपनी ने कहा कि विकसित बाजारों में लोगों का रुझान हर्बल टी की ओर बढ़ने से पारंपरिक ब्लैक टी की बिक्री प्रभावित हुई है। जबकि यूनिलीवर के चाय कारोबार में ब्लैक टी की उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि कंपनी 60 देशों में ब्लैक टी की बिक्री करती है और सालाना बिक्री से करीब 3 अरब यूरो यानी 3.3 अरब डॉलर जुटाती है।

समूह की बिक्री में फूड ऐंड रीफ्रेशमेंट कारोबार में लिप्टन चाय और हेलमैन की मेयोनेज का योगदान 40 प्रतिशत रहता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इस कारोबार को विशेषरूप से झटका लगा है क्योंकि उपभोक्ता स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा बेहतर विकल्प चुन रहे हैं। लिबरम के विश्लेषक अनुभव मल्होत्रा ने कहा कि हम इस निपटान रणनीति के संबंध में कुछ प्रगति देखकर प्रसन्न हैं, जबकि जेफेरीज के विश्लेषकों का कहना है कि इससे फूड ऐंड रीफ्रेशमेंट खंड में महत्त्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। पिछले साल जनवरी में नियंत्रण हासिल करने के छह महीने बाद जोप ने कुछ राजस्व गंवाने के बावजूद निरंतरता के लक्ष्य पर ध्यान देने की घोषणा की थी। मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि जैसा कि उन्होंने वर्णित किया था, वह 'उद्देश्य वाले ब्रांड' के रूप में ध्यान केंद्रित करते हुए यूनिलीवर के विशाल पोर्टफोलियो को और ज्यादा कारगर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह उनकी सबसे तेजी से बढ़ने वाली परिसंपत्ति है।

कमजोर बिक्री से बढ़ी चिंता

- कंपनी का शेयर 1.6 फीसदी चढ़ा, एफटीएसई में बढ़त दर्ज करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी
- कंपनी के वार्षिक राजस्व में चाय कारोबार से 3 अरब यूरो का योगदान
- चौथी तिमाही में बिक्री महज 1.5 फीसदी बढ़ी, जो एक दशक की सबसे सुस्त रफ्तार

विश्लेषकों ने कहा, भारत पर कोई प्रभाव नहीं

हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि एचयूएल ने भले ही वैश्विक स्तर पर अपने कारोबार की समीक्षा करने का निर्णय लिया है लेकिन उसका भारत के चाय कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के भारतीय चाय पोर्टफोलियो में ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, 3 रोजेज, ताजा, ताज महल और लिप्टन ग्रीन टी शामिल हैं। कॉफी (ब्रू), पैकेटबंद फूड (किसान, नॉर और अन्नपूर्णा), आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट (क्वालिटी वाल्स और मैग्नम) के साथ ये ब्रांड एचयूएल के फूड ऐंड रीफ्रेशमेंट कारोबार को एकीकृत बनाते हैं।

वित्त वर्ष 2019 के अंत में एचयूएल का राजस्व 7,131 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष के दौरान इस कारोबार का योगदान कंपनी के कुल राजस्व में 19 फीसदी और मुनाफे में 15 फीसदी रहा। जीएसके कंज्यूमर का एचयूएल में विलय पूरा होने के करीब है और उससे कंपनी का एकीकृत कुल कारोबार 10,000 करोड़ रुपये के पार हो जाएगा।

एडलवाइस के कार्यकारी उपाध्यक्ष (अनुसंधान, संस्थागत इक्विटी) अबनीश रॉय ने कहा, 'हमें नहीं लगता है कि एचयूएल भारत में अपने चाय कारोबार की बिक्री का आकलन करेगी क्योंकि वह बाजार की अग्रणी है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिस्सेदारी बढ़ाई है। यूनिलीवर द्वारा वैश्विक चाय कारोबार की रणनीतिक समीक्षा उसके कुछ परिपक्व बाजारों और पीजी टिप्स जैसे ब्रांडों के लिए है।'

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, घरेलू चाय कारोबार में एचयूएल और टाटा टी के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा है और दोनों कंपनियों में से हरेक के पास 19 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है। इस बाबत जानकारी के लिए एचयूएल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। *बीएस*

आईटीसी, इमामी का ग्रामीण बाजार पर जोर

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 30 जनवरी

- आईटीसी का 80 फीसदी नया हैंडलर आधार ग्रामीण क्षेत्र से
- इमामी ने 20 हजार से अधिक शहरों और गांवों तक बढ़ाई पहुंच
- एचयूएल का वितरण नेटवर्क सीधे तौर पर करीब 50 हजार गांवों को कवर करता है

आईटीसी और इमामी जैसी प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां ग्रामीण बाजार में सीधे तौर पर अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। इन क्षेत्रों में कमजोर ग्राहक धारणा के कारण बिक्री प्रभावित हो रही है लेकिन कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से बिक्री को रफ्तार देने में मदद मिल सकती है। इसलिए कंपनियों ने ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने की गतिविधियों के जरिये मंदी को मात देने की रणनीति बनाई है।

फिलहाल मंदी का असर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अधिक दिख रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आईटीसी ने चालू वित्त वर्ष में अपने ग्रामीण स्टॉकिस्ट नेटवर्क को दोगुना कर दिया है। इससे कम आबादी वाले क्षेत्रों तक कंपनी की पहुंच बढ़ेगी।

आईटीसी के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हमने काफी सक्रियतापूर्वक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सीधी पहुंच बढ़ाई है और मौजूदा नेटवर्क में 25 फीसदी से अधिक नए बाजारों को जोड़ा गया है।' आईटीसी का हैंडलर आधार फिलहाल 62 लाख आउटलेट का है और वह आउटलेट कवरेज में आक्रामक विस्तार के लिए निवेश कर रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 80 फीसदी नए हैंडलर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं।

इमामी लिमिटेड का अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सबसे अधिक निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में है। कंपनी ने करीब तीन साल पहले अपनी धनुष परियोजना शुरू की थी। इसके तहत दूरदराज के क्षेत्रों तक गहरी पैठ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इमामी की पहुंच देश भर में करीब 3,000 से अधिक आबादी वाले 20,000 से अधिक शहरों तक बढ़ी है।

इमामी लिमिटेड के निदेशक मोहन गोयनका ने इस समाचार पत्र से कहा, 'आउटलेट पर पॉइंट ऑफ पर्चेज विजिबिलिटी के जरिये वैन ब्रांडिंग और विजुअल मर्केंडाइजिंग ग्रामीण चैनल में वृद्धि को रफ्तार और ग्राहकों को प्रभावित करने का एक प्रभावी उपाय साबित हुई है।'

करीब 3,000 वितरकों और 6 लाख वर्ग फुट से अधिक की वाणिज्यिक परिसंपत्ति के साथ एचयूएल ने भी सीधे तौर पर ग्राहकों के लिए वितरण नेटवर्क में विस्तार को प्राथमिकता दी है। एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिका के अनुसार, 1997 में अपनी शुरुआत के बाद एचयूएल अब तक 6,000 उप-स्टॉकिस्टों को नियुक्त किया है क्योंकि उसका वितरण नेटवर्क सीधे तौर पर करीब 50,000 गांवों को कवर करता है और उसकी पहुंच करीब 25 करोड़ ग्राहकों तक है। इस प्रकार वह करीब 37 फीसदी ग्रामीण उपभोक्ताओं तक सीधे तौर पर पहुंच रही है।

ग्रामीण बाजारों में कार बिक्री के लिए सकारात्मक रुझान

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 30 जनवरी

मॉनसून तथा बेहतर फसल की बदौलत आर्थिक सुधार के संकेत के बीच ग्रामीण बाजारों में सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है और प्रमुख कार निर्माताओं के लिए यह शहरी बाजार से बेहतर आंकड़े दे रहा है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या बीएस-6 मानकों के पूरी तरह लागू हो जाने के बाद भी यह रूख बरकरार रहेगा क्योंकि इस दौरान कीमतों में तेजी आएगी तथा ग्रामीण बाजार कीमतों को लेकर काफी संवेदनशील रहता है।

देश की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) की दिसंबर 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही के दौरान ग्रामीण बाजार बिक्री में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई और कंपनी की कुल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 38 फीसदी रही। एमएसआईएल के कार्यकारी निदेशक (विपणन एवं वृद्धि) शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवधि के दौरान शहरी बाजार में कार बिक्री में 0.6-0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अच्छे मॉनसून के चलते रबी तथा खरीफ फसलों से अच्छी पैदावार से ग्रामीण क्षेत्रों की आय में तेजी आई है जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। ग्रामीण बाजार में छोटी कार की मांग बढ़ी है। श्रीवास्तव ने कहा कि बेहतर माहौल तथा इसमें बढ़ोतरी होने के बाद भी कार के बारे में पूछताछ को खरीद में बदलना चुनौती बना हुआ है। बीएस-6 मानकों के अपनाने से कीमतों में आने वाली तेजी इसका एक प्रमुख कारण है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता हुंडई मोटर इंडिया लि. में निदेशक (बिक्री एवं विपणन) तरुण गर्ग इस बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि ग्रामीण बाजार में रुझान सकारात्मक बने हैं। उन्होंने कहा, 'एक साल पहले इस ओर काफी तनाव था। भारतीय बाजार में पिछले चार-पांच वर्षों से सभी वृद्धि ग्रामीण बाजारों से आ रही है। पिछले 6-8 महीनों से रूझान काफी नकारात्मक थे लेकिन इस साल मॉनसून के अच्छा रहने से हमें एक तरह की वापसी दिखाई दे रही है।'

एनसीएलएटी जाएगी डालमिया भारत

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 30 जनवरी

डालमिया भारत सीमेंट अपनी सहायक इकाई कैलकॉम सीमेंट के खिलाफ नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के गुवाहाटी पीठ के आदेश के खिलाफ नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में अपील दायर करने की योजना बना रही है। पीठ ने कैलकॉम सीमेंट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।

मॉरिशस की कंपनी गुआरांटको लिमिटेड की शिकायत पर एनसीएलटी ने यह आदेश दिया था। इस वित्तीय लेनदार ने कंपनी पर 100 करोड़ रुपये के बकाये का आरोप लगाया है। मामले के करीबी सूत्रों ने कहा कि डालमिया भारत फिलहाल एनसीएलटी के आदेश का अध्ययन कर रही है और वह जल्द ही आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील करेगी। डालमिया भारत के एक करीबी व्यक्ति ने कहा कि अपील इस दलील पर आधारित होगी कि एनसीएलटी को कैलकॉम और गुआरांटको के बीच पहले से चल रहे विवाद के लिए ब्याज दर निर्धारित करना और मूल विवाद पर गौर करना अभी बाकी है।

एक व्यक्ति ने कहा, 'ब्याज संबंधी मुद्दों के साथ दोनों पक्षों के बीच विवाद पहले से चल रहा है। सबसे पहले उसे निपटाने की जरूरत है।'

टाटा मोटर्स का कर पूर्व लाभ 1,350 करोड़ रुपये

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 30 जनवरी

दिसंबर तिमाही में टाटा मोटर्स ने एकीकृत आधार पर लाभ दर्ज किया। जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की मालिक को लगातार छठे महीने चीन में बिक्री बढ़ने से फायदा मिला। कंपनी की आय को बेहतर बिक्री के अलावा परियोजना लागत में बचत से भी मजबूती मिली।

दिसंबर तिमाही में कंपनी का कर पूर्व लाभ 1,350 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में उसे 29,228 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान हुआ था। इस अवधि में एकीकृत स्तर पर शुद्ध लाभ 1,755.88 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में उसे 26,960.8 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ था।

कंपनी का कुल परिचालन राजस्व 71,676.07 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 76,915.94 करोड़ रुपये रहा था। ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर का राजस्व पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 6.4 अरब पाउंड पर पहुंच गया।

टाटा मोटर्स ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी पी बी बालाजी ने हालांकि कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार से चीन में मांग पर विपरीत असर पड़ सकता है और इस वित्त वर्ष के लिए मार्जिन का कुल लक्ष्य पटरी से उतर सकता है।

बालाजी ने कहा, कुछ चीजें हमें चिंतित कर रही है और सबसे बड़ी चीज चीन में कोरोनावायरस का प्रसार है। जेएलआर के लिए 3 फीसदी एबिटा मार्जिन का अनुमान जताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर वायरस के प्रसार का असर पड़ सकता है, जिस पर हम नजर रखे हुए हैं। चीन में जेएलआर की खुदरा बिक्री लगातार छठे महीने बढ़ी। इस क्षेत्र ने कुल बिक्री में 19.4 फीसदी का योगदान किया। तिमाही के दौरान जेएलआर की कुल बिक्री 2.3 फीसदी घटकर 1,41,200 वाहन रही।

ब्रिटिश सहायक ने लागत में बचत वाली परियोजना का लक्ष्य बढ़ा दिया है। जेएलआर अब चीन में 2.9 अरब पाउंड की बचत कर पाएगी जबकि पहले मार्च 2020 तक 2.5 अरब पाउंड की बचत का लक्ष्य था।

ब्रेक्सिट के असर पर टिप्पणी करते हुए बालाजी ने कहा कि ब्रेक्सिट के पहले चरण को लेकर चिंता बनी हुई है। हमें अब देखना होगा कि दिसंबर के आखिर तक अब बातचीत किस तरह की रहती है। ब्रेक्सिट के सख्त रहने का डर अब नहीं रहा है।

इस बीच, मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की कमजोर बिक्री का भारत के परिचालन पर असर पड़ा है। कंपनी ने 1,039.51 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया जबकि एक साल पहले की समान अवधि में उसे 617.62 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। एकल आधार पर राजस्व घटकर 10,842.91 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 16,207.67 करोड़ रुपये रहा था। गुरुवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.98 फीसदी टूटकर 186.20 रुपये पर बंद हुआ।

एलआईसी हाउसिंग का कर पूर्व लाभ घटा

अभिजित लेले
मुंबई, 30 जनवरी

दबाव वाले कर्ज के लिए प्रावधान में तीव्र बढ़ोतरी के कारण एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में 13 फीसदी घटकर 859.59 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का कर पूर्व लाभ 745.32 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 4.05 फीसदी की गिरावट के साथ 440.15 रुपये पर बंद हुआ।

तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 597.53 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 596.31 करोड़ रुपये रहा था। दिसंबर तिमाही में संभावित उधारी नुकसान के लिए कंपनी का प्रावधान 2,584.72 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,555.33 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी की शुद्ध ब्याज आय 18 फीसदी बढ़कर 1,228 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,043 करोड़ रुपये रही थी। शुद्ध ब्याज मार्जिन दिसंबर तिमाही में सुधरकर 2.42 फीसदी पर पहुंच गया।

कंपनी की बकाया लोनबुक 13 फीसदी बढ़कर 2,05,692 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,81,553 करोड़ रुपये रही थी। तीसरी तिमाही में कुल 13,177 करोड़ रुपये कर्ज का वितरण हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि में 12,778 करोड़ रुपये रहा था।

बजट से पूंजी बाजार के प्रतिभागियों की उम्मीदें

ऐश्ली कुटिन्हो

एलटीसीजी : साल 2018-19 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे लागू किया। एक लाख रुपये की ज्यादा के सूचीबद्ध इक्विटी के लेनदेन से होने वाले लाभ पर 10 फीसदी कर लगता है। उद्योग के प्रतिभागियों को उम्मीद है कि सूचीबद्ध इक्विटी शेयर की बिक्री पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर से छूट देगी। साथ ही सरकार ऐसी छूट के लिए निवेश की अवधि 24 महीने कर देगी यानी असूचीबद्ध शेयरों के बराबर।

डीडीटी : उम्मीद है कि सरकार कंपनी के लिए लाभांश वितरण कर समाप्त कर देगी और रियायती दर पर गैर-कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए इसे करयोग्य बना देगी। अभी कंपनी करयोग्य लाभ का 25 फीसदी या 30 फीसदी (अधिभार व उपकर समेत) आयकर चुकाती है। जब इसका वितरण शेयरधारकों को किया जाता है तो उसे 20.56 फीसदी लाभांश वितरण कर देना होता है। इसके अलावा गैर-कॉरपोरेट करदाताओं को 10 लाख रुपये से ज्यादा लाभांश पर 10 फीसदी अतिरिक्त कर चुकाना होता है। ऐसे में प्रभावी कर काफी ज्यादा है।

एफपीआई सीमा में इजाफा : बाजार के प्रतिभागी चाहते हैं कि सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए बॉन्ड में निवेश की सीमा में इजाफा करे ताकि भारत को वैश्विक बॉन्ड सूचकांक का हिस्सा बनने में मदद मिले। भारत ने पहली बार वैश्विक इंडेक्स प्रदाताओं के साथ साल 2013 में बातचीत शुरू की थी, पर बाद में सूचकांकों को शामिल करने की योजना टाल दी थी जब बॉन्ड बाजार में पूंजी प्रवाह पर लगी पाबंदी हटाने पर मतभेद हुए। वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने की प्राथमिक शर्त निवेश और निवेश निकासी पर पाबंदी न होना है।

म्युचुअल फंडों और यूलिप के बीच समानता : कर व्यवहार के मामले में यूलिप और इक्विटी म्युचुअल फंडों को एकसमान बनाए जाने की दरकार है। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया ने इक्विटी फंडों से निवेश निकासी के समय एलटीसीजी कर और एसटीटी की समाप्ति की मांग की है। उद्योग चाहता है कि इक्विटी फंडों पर दिए जाने वाले लाभांश पर लाभांश वितरण कर हटाया जाए और म्युचुअल फंड योजनाओं के बीच निवेश स्विच करने को भी पूंजीगत लाभ कर से छूट मिले।

कैटिगरी-3 एआईएफ : लंबे समय से कैटिगरी-3 एआईएफ की मांग पास थ्रू स्टेटस की है, जो सरकार ने साल 2015 में कैटिगरी-1 और कैटिगरी-2 एआईएफ को दी थी। पास थ्रू स्टेटस न मिलने का मतलब यह है कि ऐसे फंडों की आय पर फंड के स्तर पर ही कर लगाया जाएगा और कर देनदारी यूनिटधारकों पर नहीं डाली जाएगी। वे चाहते हैं कि कैटिगरी-3 एआईएफ पर लागू ज्यादा अधिभार को उचित बनाया जाए।

कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तक रख पाएंगे 26 फीसदी हिस्सा

पृष्ठ-1 का शेष

इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रवर्तकों के मताधिकार की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी रखा था। बैंक यह हलफनामा देने को भी तैयार था कि मई 2020 तक वह अपने प्रवर्तकों के मताधिकार को 20 फीसदी के स्तर तक सीमित कर देगा। उसका कहना था कि आरबीआई मुख्य रूप से इसी बात के लिए तो चिंतित है कि बैंकों के प्रवर्तकों के पास ताकत का संकेंद्रण न हो।जहां तक रिजर्व बैंक के मानदंडों का सवाल है तो एक बैंक को अपना परिचालन शुरू करने के तीन साल के भीतर प्रवर्तकों की हिस्सेदारी को 40 फीसदी तक लाने की जरूरत होती है। उसके बाद 10 वर्षों के भीतर बैंक को प्रवर्तक हिस्सेदारी 20 फीसदी और 15 वर्षों में 15 फीसदी तक लानी होती है। *(डिसक्लेमर: बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में कोटक परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है)*

बजाज ऑटो का शुद्ध लाभ 8 फीसदी बढ़ा

बजाज ऑटो का एकीकृत शुद्ध लाभ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही में 8.33 फीसदी बढ़कर 1,322.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी को 1,220.77 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

बजाज ऑटो ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी परिचालन आय 7,639.66 करोड़ रुपये रही। 2018-19 की अक्टूबर-दिसंबर अवधि में यह आंकड़ा 7,435.80 करोड़ रुपये था। इस दौरान इसमें 2.74 फीसदी की वृद्धि हुई है। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल बिक्री पांच फीसदी गिरकर 12,02,486 इकाई रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 12,59,828 इकाई थी। तीसरी तिमाही के दौरान मोटरसाइकिल बिक्री पांच फीसदी घटकर 10,27,161 इकाई रही। एक साल पहले इसी अवधि में उसने 10,78,384 मोटरसाइकलों की बिक्री की थी।

वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी तीन फीसदी गिरकर 1,75,325 रही। 2018-19 की दिसंबर तिमाही में उसने 1,81,444 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री की थी। इस दौरान, घरेलू बाजार में उसकी मोटरसाइकल बिक्री 16 फीसदी गिरकर 5,42,978 रही। हालांकि, 2019-20 की तीसरी तिमाही बजाज का निर्यात सात फीसदी बढ़कर 5,62,772 पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी तिमाही में उसने 5,24,717 गाड़ियों का निर्यात किया था। कंपनी ने कहा कि यह किसी भी तिमाही में निर्यात का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भाषा

इंडियन ऑयल का शुद्ध लाभ तीन गुना बढ़ा

एजेंसियां
नई दिल्ली, 30 जनवरी

देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) ने दिसंबर तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में तीन गुना वृद्धि दर्ज की।

आईओसी के चेयरमैन संजीव सिंह ने यहां कहा कि अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में कंपनी का एकल शुद्ध लाभ 2,339.02 करोड़ रुपये या 2.55 रुपये प्रति शेयर रहा जो पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि के 716.82 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ (0.76 रुपये प्रति शेयर) की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है।

उन्होंने कहा, 'मुनाफे में यह वृद्धि मुख्य रूप से दिसंबर तिमाही के दौरान इन्वेंट्री में बढ़ोतरी की वजह से संभव हुई, जबकि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समान तिमाही के दौरान कंपनी को इन्वेंट्री स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ा था।' कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 1,608 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री वृद्धि दर्ज की जबकि 2018-19 की तीसरी तिमाही में उसे 8,523 करोड़ रुपये के इन्वेंट्री नुकसान हुआ था। दिसंबर तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 2,695.09 करोड़ रुपये रहा।

पेट्रोल-डीजल कीमतें अप्रैल से 1 रुपये तक बढ़ेंगी : जब भारत यूरो-6 उत्सर्जन अनुकूल वाहन ईंधन के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल के शुरू से 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक बढ़ सकती हैं। अभी बीएस-4 ग्रेड के ईंधन की आपूर्ति की जा रही है और सरकार ने वाहनों सें उत्सर्जन घटाने के लिए अप्रैल 2020 से बीएस-6 ग्रेड ईंधन के इस्तेमाल का निर्णय लिया है।

ब्रेक्सिट के बाद सुधरेगी देसी आईटी फर्मों की मांग

देवाशिष महापात्र
और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 30 जनवरी

ब्रिटेन 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से औपचारिक तौर पर अलग हो जाएगा, ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियां इस देश में कारोबारी परिचालन के लिए भविष्य की निश्चित दिशा तय कर पाएंगी।

कंपनी अधिकारियों व विश्लेषकों ने हालांकि कहा कि ब्रेक्सिट पर स्पष्टता के बाद मांग में संभावित सुधार साल की दूसरी छमाही में ही प्रतिबिंबित हो पाएगा।

लंदन की ओवम रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक हंसा आयंगर ने कहा, एकमात्र चीज स्पष्ट हुई है कि ब्रेक्सिट हो रहा है। हालांकि वास्तविक चुनौतियां अभी आनी बाकी है। ब्रेक्सिट का सबसे बड़ा असर बाकी दुनिया के साथ कारोबार की ब्रिटेन की क्षमता पर होगा, जब तक कि उसके पास अलग-अलग कारोबारी करार न हो। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय आईटी कंपनियों का ब्रिटिश राजस्व दूसरी तिमाही में बढ़ेगा।

भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका के बाद ब्रिटेन दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो कुल भारतीय आईटी निर्यात 150 अरब डॉलर में करीब 17 फीसदी का योगदान करता है। एक महाद्वीप के तौर पर यूरोप की राजस्व हिस्सेदारी बड़ी आईटी फर्मों के ळिए 20 से 30 फीसदी तक है। वहीं इन्फोसिस कुल राजस्व का करीब 25 फीसदी यूरोपीय महाद्वीप से हासिल करती है जबकि टीसीएस को यहां से 30 फीसदी योगदान मिलता है। टीसीएस के राजस्व में अकेले ब्रिटेन की हिस्सेदारी 16 फीसदी है। इसी तरह विप्रो को यूरोप से 24 फीसदी राजस्व मिलता है।

हालांकि ब्रेक्सिट को लेकर अनिश्चितता ने ज्यादातर फर्मों के राजस्व की रफ्तार को धीमा किया है। टीसीएस का ब्रिटेन से राजस्व तीसरी तिमाही में 7.5 फीसदी बढ़ा, जो इससे पिछली तिमाही में 14 फीसदी रहा था। हालांकि अब कंपनी के अधिकारियों को बेहतरी की उम्मीद है।

ब्रेक्सिट की तैयारी में जुटीं भारतीय कंपनियां

देव चटर्जी
मुंबई, 30 जनवरी

शुक्रवार को यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा ब्रिटेन

- यूनाइटेड किंगडम में अच्छी खासी मौजूदगी वाली भारतीय कंपनियां भी नई स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं
- कुछ कंपनियों ने नौकरियों में कटौती की है और कुछ अपने कर्मचारियों को दूसरी जगह भेज रही हैं
- बिक्री और आपूर्ति शृंखला पर कम से कम असर पड़े, इसकी रणनीति बनाने के लिए उनके पास इस साल दिसंबर तक का समय

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की योजना के बीच यूनाइटेड किंगडम में अच्छी खासी मौजूदगी वाली भारतीय कंपनियां भी नई स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं। इसके तहत कुछ कंपनियों ने नौकरियों में कटौती की है और कुछ अपने कर्मचारियों को दूसरी जगह भेज रही हैं।

इन कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों का कहना है कि बिक्री और आपूर्ति शृंखला पर कम से कम असर पड़े, इसकी रणनीति बनाने के लिए उनके पास इस साल दिसंबर तक का समय है। ब्रिटेन की योजना दिसंबर तक यूरोपीय संघ से नए व्यापारिक सौदे पर बातचीत पूरा करने की है, जिसके बाद व्यापार शुल्क को लेकर सभी अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी।

ब्रिटेन में मौजूद भारतीय कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर ने घोषणा की है कि वह ब्रेक्सिट की वजह से 500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। कंपनी अपने वैश्विक आपूर्ति का 77 फीसदी विनिर्माण ब्रिटेन में करती है और अपने एसयूवी ब्रांड डिफेंडर का विनिर्माण स्लोवाकिया स्थानांतरित कर दिया है।

टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्त अधिकारी पीबी बालाजी ने कहा, 'हमारा ध्यान इस पर है कि दिसंबर अंत तक बातचीत किस तरह रहती है।' अनिश्चितता की वजह से पिछले कई तिमाहियों से ब्रिटेन में जेएलआर की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। टाटा मोटर्स की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर तिमाही के अंत तक कंपनी की कुल बिक्री में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 23.1 फीसदी रही। इसी दौरान यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 29.7 फीसदी रही।

अक्टूबर 2018 में जेएलआर के मुख्य कार्याधिकारी राल्फ स्पेथ ने ब्रेक्सिट के असर को लेकर आगाह किया था कि इसकी वजह से उसे संयंत्र बंद करने पड़ सकते हैं और कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि ब्रेक्सिट के कारण जेएलआर के ब्रिटेन संयंत्र की उपयोगिता स्तर कम रहने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है और मार्जिन कम हो सकता है।

टाटा स्टील से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि इसका टाटा स्टील के ग्राहकों या आपूर्ति शृंखला पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का करार किया गया है। इस बीच दोनों सरकारों के पास नए व्यापारिक सौदों पर बातचीत करने का पर्याप्त मौका होगा।

एस्सार ऑयल यूके लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ब्रेक्सिट के कारण कारोबार पर किसी तरह के असर पड़ने की आशंका नहीं है। कंपनी स्टैनलो में 1 करोड़ टन सालाना क्षमता की तेल रिफाइनरी का परिचालन करती है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारे पास दिसंबर तक का समय है और उम्मीद है कि तब तक सभी लंबित मसले हल हो जाएंगे।'

आईटी क्षेत्र भी ब्रेक्सिट की तैयारियों में जुट गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहा है कि वह अपने 1,200 कर्मचारियों को ब्रिटेन से हटाएगी। कंपनी ने कहा कि अगर दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक समझौते नहीं होते हैं तो यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच कुशल कर्मचारियों के सुगम आवाजाही में दिक्कत हो सकती है।

इन्फोसिस के अधिकारियों ने पिछले साल मई में आगाह किया था कि ब्रेक्सिट के कारण बड़ी दिक्कत हो सकती है। इन्फोसिस के सह-अध्यक्ष मोहित जोशी ने ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में कहा कि यह हमारे सभी ग्राहकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ग्राहकों ने कहा कि अनिश्चितता से उन पर असर पड़ रहा है और निवेश योजना भी प्रभावित हो रही है।

(साथ में शैली सेठ मोहिले और ईशिता आयान दत्त)

बीएस बातचीत

'निजता विधेयक में बदलाव असंवैधानिक'

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा भारत के निजता संबंधी विधेयक के मुख्य वास्तुकार न्यायाधीश **बीएन श्रीकृष्ण** ने केंद्र सरकार द्वारा निजी डेटा संरक्षण विधेयक में किए गए बदलावों पर अपनी असहमति जाहिर की। न्यायाधीश श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने इस विधेयक को तैयार किया था जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हाल ही में सदन पटल पर रखा गया। न्यायाधीश श्रीकृष्ण ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के **पवन लाल** को बताया कि सरकार द्वारा किए गए बदलाव असंवैधानिक हैं

विधेयक में किए गए किन बदलावों से आप असहमत हैं?

उन्होंने व्यक्ति के डेटा तक पहुंच बनाने से संबंधित नियंत्रण प्रणाली के नियमों को खुर्द-बुर्द कर दिया है जिसे कानून तथा संसदीय प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा किया गया यह बदलाव सरकार की निरंकुशता को दर्शाती है।

आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

क्योंकि यह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है और किसी सरकारी कार्यालय में बैठा एक अफसरशाह एक पेन चलाकर आपके सभी डेटा तक पहुंच बना सकता है।

विधेयक के मूल मसौदे में ऐसे प्रावधान नहीं थे। हम इसके लिए संसदीय प्रक्रिया का उपयोग करने के पक्ष में थे। यहां तक कि संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून को पुट्टास्वामी निर्णय के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड़ों का पालन करना होगा। (पुट्टास्वामी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के तौर पर संरक्षित किया गया है।)

इस पूरी प्रक्रिया का सार क्या है, क्या इसका कोई निदान है?

सार यह है कि इस तरह का विधेयक नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता और यह बहुत खतरनाक है। इसे चुनौती दी जा सकती है और व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकते हैं। हालांकि यह फिर एक लंबी प्रक्रिया होगी और अहम बात यह है कि यह कानून हमारी रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था जिसे नागरिकों तथा सरकारों, सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। कानून इसलिए बनाए जाते हैं जिससे सरकार भी इससे इतर कदम न उठा सके।

पेंशन की जिम्मेदारी ले सरकार

रेलवे के 15 लाख पेंशनभोगियों की 50,000 करोड़ रुपये देनदारी

ज्योति मुकुल
नई दिल्ली, 30 जनवरी

पीपीआर के राडार पर

समर्पित मालवहन गलियारे

गलियारा	लंबाई (किलोमीटर में)	रिटर्न* (%)	लागत (करोड़ ~)
हावड़ा-मुंबई	2,328	28.4	1,60,959
दिल्ली-चेन्नई	2,328	21.1	1,67,062
खडगपुर-विजयवाड़ा	1,115	34.7	74,750

*रिटर्न की दर

रेल मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि वह उसके वित्तीय दबाव को देखते हुए अनुमानित रूप से 50,000 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी ले ले। रेलवे 2024 तक क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है, जो संभवत: इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी हो जाए और उसका परिचालन अनुपात पिछले साल से भी खराब रहने की संभावना है।

भारतीय रेलवे ने प्रमुख परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें समर्पित मालवहन गलियारे, तेज रफ्तार रेलवे और सिगनलिंग का उन्नयन शामिल है। इसका मकसद माल ढुलाई में हिस्सेदारी बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना है, जो अभी 25 प्रतिशत है।

रेलवे में करीब 15 लाख पेंशनधारक हैं। अन्य सरकारी विभागों के विपरीत रेलवे के पेंशनधारकों का भुगतान रेल राजस्व से होता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वाईके यादव ने बुधवार को कहा, 'हमने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि यह देनदारी पूरी तरह से या चरणों में अपने ऊपर ले। अन्यथा हमें 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये का घाटा होगा।'

रेलवे ने इस साल परिचालन मुनाफा 95 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है, जो 2018-19 में 98.4 प्रतिशत और 2019-20 में 97.29 प्रतिशत था। बजट अनुमान में पुनरीक्षित परिचालन अनुपात बजट की तुलना में ज्यादा रहने की उम्मीद है। यादव ने कहा कि रेलवे अगले 2 महीनों में खर्चों को तार्किक बनाने व कमाई बढ़ाने की कवायद कर रहा है, जिससे कि वित्तीय दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे साल के अंत तक 1.9 से 2 लाख करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है, जिसमें से 25 प्रतिशत पेंशन संबंधी देनदारी के भुगतान में जाएगा। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार गलियारे, समर्पित मालवहन गलियारे व मल्टीट्रैकिंग से क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

डेटा सेंटर में संभावना तलाश रहीं इंजीनियरिंग कंपनियां

अमृता पिल्लई
मुंबई, 30 जनवरी

भारत के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार में इंजीनियरिंग कंपनियां कारोबार की संभावना तलाश रही हैं। इस नए कारोबारी क्षेत्र में 8,5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। ऐसे में ये कंपनियां इन केंद्रों को बनाने व उनके रखरखाव के क्षेत्र में अवसर तलाश रही हैं।

स्टर्लिंग ऐंड विल्सन में ग्रुप हेड, बिजनेस डेवलपमेंट और डेटा सेंटर बिजनेस के मुख्य कार्याधिकारी प्रसन्ना श्रंबले ने कहा, 'इंजीनियरिंग में डेटा सेंटर इस समय केंद्र में है।' श्रंबले को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस क्षेत्र का सालाना टर्नओवर 400 करोड़ रुपये पार कर जाएगा।

लार्सन ऐंड टुब्रो और केईसी इंटरनैशनल दो अन्य कंपनियां हैं, जो इस कारोबार में संभावना तलाश रही हैं। एलऐंडटी विभिन्न परियोजनाओं पर पहले से ही काम कर रही है, वहीं केईसी इंटरनैशनल को उम्मीद है कि जल्द ही उसे बड़ी परियोजना मिल जाएगी।

केईसी इंटरनैशनल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विमल केजरीवाल ने कहा, 'डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में हमने सबसे कम बोली लगाई है।' कंपनी के अधिकारी ने कहा कि उनकी कंपनी के लिए सिविल बिजनेस, केबल बिजनेस और स्मार्ट सिटी सेग्मेंट में दिलचस्पी के हिसाब से डेटा सेंटर सबसे बेहतर कारोबार है। उन्होंने कहा, 'यह हमारे पारेषण एवं वितरण (टीऐंडडी) कारोबार में भी काम लाता है क्योंकि डेटा सेंटर पॉवर केंद्रित हैं।'

एक घरेलू ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'इन केंद्रों को बनने में सालाना 4,000 करोड़ रुपये के कारोबार की संभावना है, जबकि संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे डीजी सेट आदि में 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। इन्हें बनाने में ठेके के काम के क्षेत्र में भी अवसर है। पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं क्योंकि इसमें हार्डवेयर की जरूरतें पड़ती हैं। इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियां सीमित हैं क्योंकि ज्यादातर हिस्सा आयातित है।'

उद्योग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इंजीनिरिंग क्षेत्र के लिए डेटा सेंटर में बाजार का आकार करीब 2.7 अरब डॉलर का है, जो 2024 तक बढ़कर 4 अरब डॉलर होने की संभावना है। सरमबले ने कहा, 'इस क्षेत्र में प्रवेश करने में हम ज्यादा प्रतिस्पर्धा देख रहे हैं यह तेजी से बढ़ता उद्योग है।' कुछ पूंजीगत वस्तु कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि इस कारोबारी क्षेत्र में परिचालन शुरू होने पर सालाना 200 करोड़ रुपये कारोबार हो सकता है।

व्यक्तिगत कर बढ़ाना हमेशा रहा कठिन लक्ष्य

'अब हम चाहते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ऐसे में हमने कंपनी अधिनियम के तहत आने वाली सभी कंपनियों के लिए समान नियम की कवायद की है... और व्यक्तिगत आयकर...मेरी इच्छा है कि इस मामले में खुद से निपटा जाए क्योंकि मैंने ऐसा किया है।'
निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री

मोदी सरकार कभी भी व्यक्गित आयकर संग्रह के मामले में बजट अनुमान हासिल करने में सफल नहीं रही है। सिर्फ नोटबंदी वाला साल 2016-17 इसका अपवाद रहा है। इस वित्त वर्ष (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) में भी यह लक्ष्य कठिन नजर आ रहा है क्योंकि नवंबर तक इस मद में कर संग्रह महज 7.2 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि लक्ष्य पूरा करने के लिए अब 23.4 प्रतिशत बढ़ोतरी की जरूरत है। नवंबर तक कर संग्रह का सिर्फ 47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सका है। यह सही है कि ज्यादातर संग्रह वित्त वर्ष 2020 के आखिर तक आना है,लेकिन हासिल किए गए और लक्ष्य में अंतर बहुत ज्यादा है। पिछले साल नवंबर तक लक्ष्य का 47 प्रतिशत कर संग्रह ही हुआ था, लेकिन कर संग्रह 68,000 करोड़ रुपये कम रहा।

मोदी सरकार के कार्यकाल में स्थिति

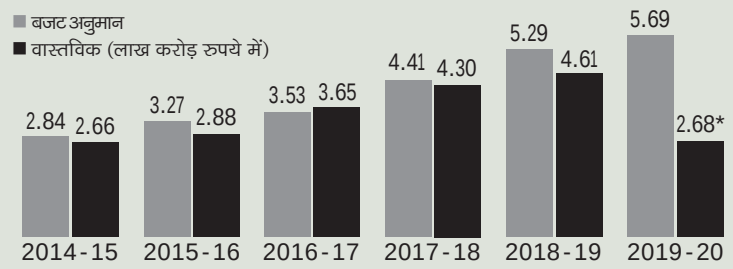

*नवंबर तक
स्रोत: बजट, महालेखा नियंत्रक

एनसीसीडी के सीईओ ने दिया इस्तीफा

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 30 जनवरी

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान निजी क्षेत्र से लिए गए कुछ शेष अधिकारियों में से एक पवनेश कोहली ने कार्यकाल खत्म होने के पहले ही नैशनल सेंटर फार कोल्ड चेन डेवलवमेंट (एनसीसीडी) के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।

कोहली की नियुक्त संप्रग सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जिन्होंने शुक्रवार को अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले 19 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था।

कोहली ने एनसीसीडी में सरकार के बाहर से पहले सीईओ और मुख्य सलाहकार का पदभार 2012 में संभाला था। कहा जा रहा है कि वह पिछले कुछ साल से इस निकाय की कार्यप्रणाली और जिस तरह से इसके मामलों को देखा जा रहा था, उससे नाखुश थे।

एनसीसीडी में पदभार संभालने के पहले कोहली गति लिमिटेड, आर्शिया इंटरनैशनल और अन्य प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनियों में शीर्ष पद पर रह चुके थे।

माइक्रोइंश्योरेंस की कवरेज राशि में बढ़ोतरी किए जाने की सिफारिश

सुब्रत पांडा
मुंबई, 30 जनवरी

नियामक को सिफारिशें

- माइक्रोइंश्योसेंस पॉलिसी के कवरेज की राशि मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाए
- जनरल या स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम वापसी का विकल्प
- माइक्रोइंश्योरेंस योजनाओं खासकर जीवन बीमा पॉलिसी के मामले में स्टांप शुल्क माफ किया जाए
- जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी की दीर्घावधि के लिए अनुमति हो

माइक्रोइंश्योरेंस पर बीमा नियामक की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें समिति ने माइक्रोइंश्योसेंस पॉलिसी के कवरेज की राशि मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। साथ ही कहा है कि जनरल इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम वापसी का विकल्प होना चाहिए।

नियामक को सौंपी सिफारिश में समिति ने कहा है, 'चर्चा के आधार पर ऐसा लगता है कि प्रीमियम की वापसी एक अहम फीचर है, जिससे उपभोक्ताओं के इस वर्ग को ज्यादा मूल्य मिलता है।' समिति ने कहा है कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जिनका सामान्यतया सालाना नवीकरण होता है, उन्हे दीर्घावधि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

माइक्रोइंश्योरेंस खासकर कम आमदनी वाले लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। उनके लिए वहनीय बीमा उत्पादों से उन्हें अपने वित्तीय नुकसान की भरपाई में मदद मिलती है। इसमें गरीबों के लिए सतत जीविका के समर्थन का वादा होता है।

समिति ने कहा है, 'बीमा क्षेत्र के उदारीकरण और सरकार की योजनाओं ने माइक्रोइंश्योरेंस के लिए नए अवसर मुहैया कराए हैं, जिससे वे बड़ी संख्या में गरीबों तक पहुंच सकते हैं, जिनमें अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं।'

बहरहाल इस क्षेत्र में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें गरीबों द्वारा भविष्य के लिए भुगतान को लेकर हिचकिचाहट शामिल है। उन्हें ऐसी समस्या के लिए भुगतान करना होता है, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के दौरान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा कवर की निरंतरता बनाए रखने के लिए नियमित भुगतान भी एक मसला है क्योंकि उनकी आमदनी की कोई निश्चितता नहीं होती है। इसके साथ ही गरीब लोग तमाम मौजूदा बीमा उत्पादों की उपयोगिता को समझ नहीं पाते और सेवाओं की गुणवत्ता भी खराब होती है, जिसकी वजह से वे नवीकरण नहीं कराते हैं।

प्रमुख सिफारिशों में समिति ने कहा है कि माइक्रोइंश्योरेंस योजनाओं खासकर जीवन बीमा पॉलिसीज के मामले में स्टांप शुल्क माफ किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 289 रुपये प्रीमियम पर स्टांप शुल्क 40 प्रतिशत है, जो बीमा राशि का करीब 14 प्रतिशत है। समिति ने कहा है कि जनरल इंश्योरेंस सामान्यतया छोटे आकार की पॉलिसी होती हैं, जिन पर स्टांप शुल्क में छूट देने पर प्रीमियम की राशि कम होगी।

समिति ने जनरल और स्वास्थ्य बीमा के माइक्रोइंश्योरेंस उत्पादों पर कैपिटल रिजर्व की जरूरत, प्रबंधन जरूरत पर व्यय में ढील देने की भी सिफारिश की है।

इसमें बीमा कराने वाले के लिए मूल्य के लचीलेपन की सिफारिश की गई है, जहां उन्हें परियोजना पेश किए जाने की तिथि के एक साल के भीतर एक निश्चित सीमा के दायरे में मूल्य में कमी या उसे बढ़ाने की छूट हो।

समिति ने रोजाना, पाक्षिक, मासिक या तिमाही किस्तों में सिंगल प्रीमियम के भुगतान की वकालत की है। समिति ने कहा है, 'हमें इस बात की भी संभावना तलाशनी चाहिए कि रोजाना की मजदूरी के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से बचत के लाभ को बांटा जाए, जो अंशदान की राशि के मुताबिक हो।'

वितरण के मोर्चे पर समिति ने कहा है कि माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई), जो मास्टर पॉलिसीधारक हैं, उन्हें कॉर्पोरेट एजेंट बनने की जरूरत है, अगर वे उनसे कमीशन हासिल करना चाहती हैं। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि माइक्रोइंश्योरेंस उत्पादों को सरल बनाए जाने की जरूरत है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को उसके बारे में जानकारी हो और वह ग्राहक समझ सके।

बीएस सूडोकू 3652

	2	5	3		1			
								2
8		1			6	4		
	1	8		3			7	
5								3
	7			1		9	6	
		3	8			5		1
9								
			6		4	3	2	

परिणाम संख्या 3651

3	4	1	2	8	5	7	9	6
9	2	8	7	6	3	1	4	5
5	6	7	1	9	4	3	8	2
7	9	3	8	4	2	5	6	1
8	5	2	6	7	1	4	3	9
6	1	4	5	3	9	2	7	8
2	7	9	3	5	6	8	1	4
4	8	5	9	1	7	6	2	3
1	3	6	4	2	8	9	5	7

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान
★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

दिल्ली
सराफा : दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपये की बढ़त के साथ 41,524 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 737 रुपये की बढ़त के साथ 47,392 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बुधवार को यह 46,655 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 41,124 रुपये प्रति दस ग्राम रहा था। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ 71.47 प्रति डॉलर पर था। वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी दोनों में बढ़त रही। सोना बढ़त के साथ 1,582 डॉलर प्रति औंस पर था, जबकि चांदी भी लाभ के साथ 17.72 डॉलर प्रति औंस पर चल रही थी।

कानपुर
गेहूं लूज 2000/2010, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250,सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1550, सरसों खल 2100/2150, पामोलिन 1550/1600, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1525/1575, अलसी 6500/6600,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3200/3250, चावल (सोना) 2800/2850,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1375, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1445, फ्लैक 1400, डीएमओ 985, टरपीन लैस बोल्ड 1458

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1180/1200, खुरपा 1030/1060,चाकू 1050/1100, रसकट 920/925, शक्कर 1180/1200, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3315, सिहोरा 3300, बुंदकी 3260, बुढ़ाना 3325, शामली ×, चीनी हाजिर 3500/3600

हापुड़
गुड़ (40 किलो): चौरसा 1000/1050, खुरपा 1000/1015, रसकट 920/935, चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, सरसों 4100/4150, खल: सरसों 2100/2200, बिनौला 2300/2450, चूरी: अरहर 2000/2050, चना 2200/2300, छिलका :चना 2200/2250, चोकर: (50 किलो) 980/985

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3700/3750, जौ 2100/2125, सरसों लूज 3950/4000

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7200/7300, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1825/1835, चना 4100/4200, काबली चना 5000/6000, मूंग 7000/7200, मोठ 6000/6100, रायडा 3700/3800, मूंगफली 4500/4600, सींगदाना 6000/6500, जीरा 15500/17000, मगज तरबूज 12800/13000, तरबूज बीज ×

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5200/5300, गेहूं (मिल) 2080/2100, मक्की 2100/2115, बाजरा 1800/1810, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 2800/2900, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4440/4450, सरसों एक्सपेलर निवाई 8650, कोल्हू कच्ची घानी टोंक 8800, राइसब्रान डिऑयल्ड कंटीन्यूअस 1400, डीओसी (टन): सरसों जयपुर 16500, कोटा 15800,अलवर 15000, निवाई 15500

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)115, राइसब्रान (अखाद्य) 112, खल सरसों 1900, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1100, लाल 1100, कंटीन्यूअस 1200, सरसों (टन) 16100, अनाज: गेहूं 2080/2085, आटा (50 किलो)1155, मैदा 1250, चोकर (49 किग्रा) 1050, चोकर (30 किग्रा) 630, मक्की बिहार 2100/2110

फाजिल्का
गेहूं 2000/2010, सरसों 4200/4250 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4130, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500, जे-34 (चिलकी) 3400/3450

भाषा/एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 296

बैंकरों का बचाव

सरकारी क्षेत्र के बैंकर ऋण देने संबंधी निर्णय लेने में अनिच्छुक नजर आते रहे हैं क्योंकि ऋण के फंसे हुए कर्ज में तब्दील होने पर उन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई का खौफ सताता है। आखिरकार सरकार ने बैंकरों को अनावश्यक प्रताड़ना से बचाने की अपनी बात पर अमल करने का फैसला कर लिया है। यह स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि भय के माहौल के कारण ऋण प्रवाह में गिरावट आई थी और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे। बैंकरों के मन में यह धारणा बन गई थी कि जांच के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव निष्क्रियता है। सरकार ने इस सप्ताह घोषणा की कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया है और शासकीय सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। सरकार ने अधिक मूल्य की धोखाधड़ी के लिए वर्ष 2015 के फ्रेमवर्क में भी संशोधन किया है। यही कारण है कि सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्याधिकारियों को अलग-अलग समय सीमा के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। सरकार ने सरकारी बैंकों के बोर्ड को सशक्त बनाया है ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्रों द्वारा निर्धारित विभिन्न टाइम लाइन का अनुपालन करने की व्यवस्था बना सकें। इसके अलावा बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों के सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है ताकि 50 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की जांच की जा सके जिनमें महाप्रबंधक और उससे ऊंचे पदों पर आसीन लोग शामिल हों। सलाहकार बोर्ड मामलों की जांच शुरू होने के पहले इनका परीक्षण करेगा। इतना ही नहीं सरकार ने बैंकों से वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करने को भी कहा ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा आंतरिक सतर्कता के मामलों की निगरानी की जा सके। ऐसे मामलों को हल करने में देरी होने का असर बैंकों के आंतरिक माहौल पर पड़ता है और यह क्षमता को भी प्रभावित करता है।

ये सारे कदम सही दिशा में उठाए गए हैं और इनसे सरकारी बैंकरों के बीच व्याप्त भय दूर होना चाहिए। निश्चित तौर पर ऋण देने के लिए सद्भावनापूर्वक या दुर्भावनापूर्वक लिए गए निर्णयों के बीच अंतर कर पाना आसान नहीं है। संभव है कि तमाम प्रक्रियाओं का उचित पालन करने के बावजूद ऋण देने का निर्णय गलत साबित हो जाए। ऐसे में जांच शुरू करने के पहले शुरुआती परीक्षण करने से बैंकरों की मदद हो सकती है। बहरहाल, यह दलील देना कठिन है कि इतने कदम उठाना भर पर्याप्त होगा। आमतौर पर कानूनी बचाव हमेशा जांच एजेंसियों को जांच शुरू करने या गिरफ्तारी करने से नहीं रोकते। इसके अलावा सरकार को व्यापक तस्वीर पर भी नजर रखनी चाहिए। सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी और फंसे हुए कर्ज के मामले केवल भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हैं। जैसा कि देश में बैंकिंग की प्रगति और रुझानों से संबंधित आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है, वर्ष 2018-19 में बैंकों में धोखाधड़ी के 90 फीसदी मामले सरकारी बैंकों में हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों और प्रक्रियात्मक जोखिम से निपटने की अपर्याप्तता साफ नजर आती है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकारी बैंकों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि ऋण देने संबंधी जोखिम का आकलन करने के लिए क्षमता विकसित की जा सके। सुधारों के अभाव में सरकारी बैंक धोखाधड़ी और जांच की आशंका में जीते रहेंगे। चाहे भले ही सरकार सुरक्षा के कितने भी उपाय कर दे। चूंकि बैंकिंग तंत्र में सरकारी बैंकों का दबदबा है इसलिए ऋण देने में उनकी अक्षमता आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। यह बात अलग है कि अब उनकी बाजार हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। सरकारी बैंकों में सुधार की तमाम वजह मौजूद हैं। सरकार इनमें निरंतर पूंजी नहीं डालती रह सकती।

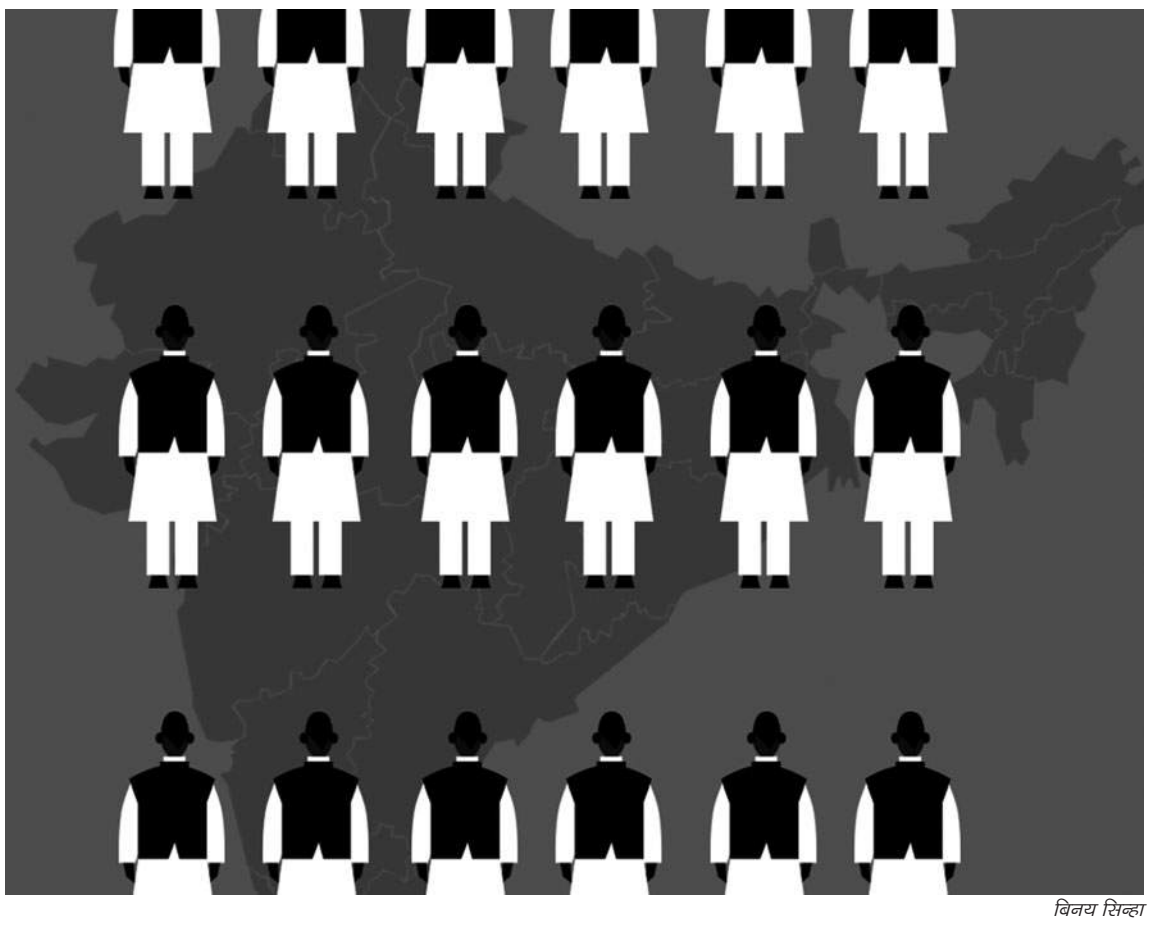

बिनय सिन्हा

विभाजनकारी हो सकता है उत्तर-दक्षिण का अंतर

राष्ट्रीय सौहार्द बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि राजस्व आवंटन तथा संसदीय सीटों की संख्या निर्धारित करने के मामले में सन 1971 की जनगणना को ही मानक बनाए रखा जाए। बता रहे हैं जैमिनी भगवती

सन 1990 के दशक के आरंभ में आर्थिक सुधारों की शुरुआत होने के बाद के तीन दशकों में दक्षिण भारत के राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में उत्तर भारत के बड़े राज्यों की तुलना में ज्यादा इजाफा हुआ है। सन 1990-91 में कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में क्रमश: 1.7 और 1.3 गुना ज्यादा थी। वर्ष 2017-18 तक यह अंतर बढ़कर 4.7 और 3.3 गुना हो चुका था। यह सिलसिला जारी है।

एक के बाद एक वित्त आयोगों द्वारा किए गए कर राजस्व आवंटन की बात करें तो यह निरपवाद रूप से विभिन्न राज्यों की आबादी से संबंधित रहा है। उदाहरण के लिए 14वें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में कहा गया है कि जहां करों के बंटवारे तथा अन्य अनुदान देने की बात हो वहां आयोग को आमतौर पर सन 1971 की आबादी के आधार को निर्धारक मानना चाहिए। हालांकि कहा यह भी किया गया कि आयोग सन 1971 के बाद आबादी के स्वरूप में आए बदलाव को भी ध्यान में रख सकता है।

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के खंड 8 का शीर्षक है 'केंद्रीय कर राजस्व की साझेदारी' और इसमें कहा गया है कि 'हालांकि हमारा मानना है कि आबादी के पुराने आंकड़ों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है लेकिन हम विचारणीय विषयों के दायरे से बंधे हुए हैं।'

व्यक्तिगत स्तर पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच कर राजस्व की साझेदारी को लेकर मतभेद रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में बदलाव करके कहा गया है कि राज्यों को आवंटन के पहले कुल राजस्व के एक हिस्से को बाहरी रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर होने वाले व्यय के लिए अलग किया जाना चाहिए। कुछ राज्य सरकारों ने इसकी जमकर आलोचना की। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आयोग के विचारणीय विषयों में चुनिंदा बदलाव करना आवश्यक था।

अतीत में वित्त आयोगों ने देश की सुरक्षा को खतरे को केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन करते समय ध्यान में रखा था। अभी हाल ही में राज्यों ने यह मांग की कि उन्हें उन उपकरों और अधिभार में से हिस्सा मिलना चाहिए जो केंद्र सरकार ने एकत्रित किए हैं। हालांकि संविधान में उल्लिखित मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक अभी केंद्र सरकार ऐसे राजस्व को पूरी तरह अपने पास रख सकता है। दिसंबर 2019 में जब जीएसटी परिषद में असहमति बनी और लॉटरी पर कराधान को लेकर एक निर्णय पर मतदान हुआ तो ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि इससे पहले जीएसटी परिषद के तमाम निर्णय आम सहमति से हुए थे।

15वें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में यह भी कहा गया है कि 'उसे अपनी अनुशंसाएं करते समय सन 2011 की आबादी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।' सन 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी देखें तो भी उत्तर भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, दक्षिण भारत के राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम थी। इसका परिणाम 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तर भारत के राज्यों को किए जाने वाले राजस्व आवंटन में इजाफे के रूप में सामने आ सकता है।

जाहिर है आवंटित राशि 14वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि की तुलना में अधिक होगी। जाहिर है इससे देश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद राज्यों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है।

मेरी समझ यह कहती है कि सन 1971 की आबादी के आंकड़ों को वित्त आयोग द्वारा किए जाने वाले आवंटन से जोड़ना उत्तरी भारत के राज्यों के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा।

यदि उत्तर भारत के बड़े राज्य बेहतर विकास प्रबंधन करने में सफल रहते तो उनकी आबादी में तेज इजाफा शायद उनके लिए लाभप्रद साबित होता। राज्यों के साथ 'निष्पक्ष' व्यवहार किया जाना चाहिए लेकिन अतीत का कमजोर आर्थिक प्रदर्शन उनके बीच प्राथमिकता देने वाले और पक्षपात करने वाले व्यवहार का कारण नहीं होना चाहिए।

चाहे जो भी उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक लोग अस्थायी या स्थायी तौर पर उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में रहने चले जाते हैं। संभव है कि उक्त तरीका जो 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित है, उसे 15वें वित्त आयोग द्वारा अपना लिया जाए। खासतौर पर यह देखते हुए कि आबादी के भार और जनांकीय बदलाव के संकेतकों को अलग-अलग पेश किया जाना चाहिए।

पिछले कुछ समय से दक्षिण भारत के राज्यों में इस बात को लेकर चिंता का वातावरण रहा है कि नए सिरे से परिसीमन की कवायद होने के बाद कैसे लोकसभा में उनकी सीटों की तादाद में कमी आएगी। सन 2002 में हुए 84वें संविधान संशोधन के अनुसार संसदीय क्षेत्रों का यह पुनर्आवंटन सन 2031 की जनगणना के मुताबिक किया जाना चाहिए (इंडियाज इमर्जिंग क्राइसिस, लेखक: मिलन वैष्णव और जेमी हिंटसन)।

अटकल यह है कि दक्षिण भारत को लोकसभा सीट के मामले में उत्तर भारत के हाथों 45 सीटों का नुकसान हो सकता है। स्पष्ट है कि दक्षिण के राज्यों को यह बात कतई स्वीकार्य नहीं होगी।

केंद्र सरकार के मौजूदा इरादों को लेकर अशांत होने की वजह नहीं है। बहरहाल, हकीकत यह है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों को धन आवंटित करने की बात से अवश्य राज्यों में चिढ़ पैदा हो सकती है। अब से 10 वर्ष बाद यानी 2031 में यदि दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीट कम की जाती हैं तो उनमें भारी नाराजगी पैदा होगी। हालांकि कम प्रति व्यक्ति आय वाले उत्तर भारत के राज्यों की प्रतिक्रिया में भी कोलाहल सुनाई पड़ सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय सौहार्द के लिए बेहतर यही होगा कि अगले तीन दशक तक एक बार फिर संसद सदस्यों की तादाद और संसाधनों का आवंटन, दोनों मामलों में सन 1971 की जनगणना को ही मानक रखा जाए।

क्या लोकलुभावन होगा वर्ष 2020 का बजट ?

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

इस बार यदि सरकार वित्त अधिनियम में पूरा ध्यान राजकोषीय सुधारों पर केंद्रित करे और संसद के दोनों सदनों से पारित विभिन्न अन्य कानूनों के विभिन्न सूचीपत्रों के माध्यम से होने वाले पुनर्लेखन को समाप्त करे तो अधिक बेहतर होगा।

आम बजट करीब आ गया है और ऐसी चर्चा बढ़ने लगी है कि वित्त विधेयक 2020 में 'लोकलुभावन' उपायों को तवज्जो दी जाएगी। कौन से कदम 'लोकलुभावन' हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन्हें लोकलुभावन कौन मानता है? आमतौर पर इसका अर्थ होता है 'अन्य लोगों' के समर्थन में उठाए गए कदम। जब अंग्रेजी मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे कदम जिनसे किसानों और वेतनभोगी लोग लाभान्वित होंगे। उदाहरण के लिए मानक कटौती में इजाफा, कृषि क्षेत्र में ज्यादा सब्सिडी, फैक्टरियों में रोबोट के इस्तेमाल पर कर लगाना आदि। यदि किसानों और वेतनभोगियों की दृष्टि से देखा जाए तो 'अन्य' का अर्थ होता है उद्योग और अमीर तबका। इनके लिए मददगार कदमों में प्रत्यक्ष कर दरों में कमी, वृद्धि के लिए अधिक निवेश और अंततः गरीबों के लिए ट्रिकल डाउन प्रभाव की अपेक्षा।

इस वक्त दो चुनौतियां हमारे सामने हैं। पहली, तेजी से बढ़ती असमानता और असमान कर नीति। अप्रत्यक्ष कर जहां अमीर और गरीब एक समान कर चुकाते हैं, वह अभी भी हमारे कर राजस्व में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। जबकि प्रत्यक्ष कर जो सीधे कर चुकाने वाले की क्षमता से जुड़े हैं और आय के समानुपाती होते हैं, उनका इस्तेमाल राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में किया जाता है और अधिकाधिक फंड समाज के हाथ में रखे जाते हैं। प्रत्यक्ष कर में पहले ही काफी राहत दी जा चुकी है। खासतौर पर कारोबारी जगत को राहत दी गई है। इससे कॉर्पोरेट जगत को अधिक आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब उसे देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है, इसके बावजूद हमारे यहां अरबपति तैयार होने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। अरबपतियों की तादाद लगातार बढ़ने के बावजूद देश के सामाजिक क्षेत्र में संस्थागत फंडिंग लगातार कम हो रही है।

हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि संपत्ति की असमानता और उसके कारण आ रही असमता सामाजिक क्षेत्र पर कई असाधारण प्रभाव डालेगी। इससे संबंधित सवालों का हल कड़े राजकोषीय सुधारों में निहित है। केवल कर अधिकारियों का भय उत्पन्न करके कर अनुपालन सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि कर नीति के लिए क्या महत्त्वपूर्ण है। खराब राजकोषीय नीति के सख्त नियमन से वह हासिल नहीं किया जा सकता है जो समझदारी भरी राजकोषीय नीति से हासिल हो सकता है। आज इस मोर्चे पर होने वाली बहस का ध्रुवीकरण हो चुका है। असमानता का जिक्र करते ही एक ओर से 'वामपंथी' होने का आरोप जड़ दिया जाता है तो दूसरी ओर प्रवर्तन में सुधार की बात करते ही सांठगांठ का आरोप लगाया जाता है।

सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट में एक छेद नजर आ रहा है। जाहिर है इन बैंकों को नए सिरे से पूंजी की आवश्यकता होगी। इसे लोकलुभावन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हालांकि इसमें भी बैंकों को उस पूंजी की फंडिंग की जाती है जो वे उद्योगों को ऋण देने में गंवा चुके होते हैं। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसे कि कृषि ऋण माफी की योजना। इसके अलावा कई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान खासतौर पर व्यवस्थागत दृष्टि से अहम संस्थान विफल हो रहे हैं। इनसे निकलने वाले सबक बताते हैं कि संचालन की नाकामियों में इजाफा हुआ है और इनके संस्थागत मूल्यों को क्षति पहुंची है। कई बार नियंत्रण ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जिनके पास कोई पद तक नहीं होता। आखिरकार किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। सुधारों की आवश्यकता संस्थानों के सहयोग के लिए धन जुटाने की आवश्यकता से कहीं अलग है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारोबारी संचालन में गहन सुधारों के बिना उनमें नई पूंजी डालने का कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा। सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी का निगमीकरण करने और बैंकों के कारोबारी प्रशासन को कंपनी कानून के अनुरूप किए बिना हमें इसकी काफी कीमत चुकानी पड़ रही है। कंपनी कानून भी सन 2013 के बाद से काफी लंबा सफर तय कर चुका है। दरअसल सरकारी बैंकों का संचालन जो बैंक राष्ट्रीयकरण कानून में तथा अन्य बैंकों के विधानों में संहिताबद्ध है, वह अप्रचलित ढंग का और बेतरतीब है।

आखिर में इस बार यदि सरकार वित्त अधिनियम में पूरा ध्यान राजकोषीय सुधारों पर केंद्रित करे और संसद के दोनों सदनों से पारित विभिन्न अन्य कानूनों के विभिन्न सूचीपत्रों के माध्यम से होने वाले पुनर्लेखन को समाप्त करे तो अधिक बेहतर होगा। ऐसा रुख अपनाना सही नहीं है जहां धन विधेयक के माध्यम से लोकसभा को राज्य सभा की स्वीकृति के लिए रखे विभिन्न कानूनी प्रावधानों को नकारने का अधिकार दे दिया जाता है। यह आम बजट की कवायद के मुख्य उद्देश्यों से ध्यान हटा देता है। हालिया अनुभव यही बताते हैं कि यह उम्मीद भी व्यर्थ हो सकती है लेकिन यदि व्यर्थ होने की यह अपेक्षा गलत साबित हो तो यह एक सुखद आश्चर्य ही होगा।

(लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानाफूसी

सिन्हा से नाराजगी

भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेता शत्रुघ्न सिन्हा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की करीबी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने लखनऊ में सपा मुख्यालय में यादव के साथ मंच साझा किया। अभिनेता से राजनेता बने सिन्हा ने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का दामन छोड़ दिया था। वह पटना साहब सीट से चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ से सपा की प्रत्याशी थीं लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णन ने ट्विटर के माध्यम से सिन्हा पर हमला बोला था कि वह पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी सिन्हा की आलोचना करते हुए कहा था कि ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए।

बिहार में तीसरी ताकत

जनता दल (यूनाइटेड) ने बुधवार को पार्टी उपाध्यक्ष और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तथा पूर्व राजनयिक पवन वर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। पार्टी ने कहा कि दोनों नेता पार्टी विरोधी वक्तव्य दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक किशोर बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं जो आगामी सितंबर-अक्टूबर में होने हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता भी तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी के उपेंद्र यादव तथा अन्य नेता भी उस तीसरी शक्ति के साथ आ सकते हैं जिसे किशोर बिहार में आकार देना चाहते हैं। इसमें राजद के विद्रोही, कुछ छोटे दल और वाम धड़ा शामिल हो सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता बिहार का अपना दौरा शुरू करने वाले हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद जेल में हैं और बीमार हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव से नाता तोड़कर जदयू और भाजपा गठबंधन के खिलाफ एक गठबंधन का नेतृत्व करेगी?

प्रशांत किशोर

आपका पक्ष

देश के भविष्य का बने भविष्य

छात्र वर्ग के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। उनकी अपनी अनेक समस्याएं हैं। इनमें प्रमुख आर्थिक असमानता है। गांवों के संपन्न किसान या व्यवसायी की संतान अगर अध्ययनशील है तो शहर में भी आसानी से शिक्षा अर्जित की जा सकती है। मगर गरीब के घर में पुत्र को वरीयता दी जाती है। भले ही पुत्री अधिक कर्मठ और मेधावी क्यों न हो। इससे उनके अंदर असंतोष की भावना पनपती है। युवाओं के लिए बेरोजगारी भी एक प्रमुख समस्या है। आज की शिक्षा का ढांचा ऐसा कोई दावा नहीं कर पाता कि डिग्री पाकर भी छात्र अपने लिए एक नौकरी पा सकता है। जब युवा वर्ग डिग्रियों का बंडल लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर धक्के खाता है तो वहां भी असंतोष ही हाथ लगता है। युवा वर्ग की और भी अनेक समस्याएं हैं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी उनका समाधान करना है। भले ही वर्तमान सरकार ने इस विषय में कई कदम उठाए हैं। मगर इस विषय पर और भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। शिक्षा को भी रोजगारोन्मुख बनाना होगा। शिक्षा ऐसी हो जिससे आर्थिक असमानता, असंतोष दूर हो और युवाओं के चरित्र निर्माण में सहायक हो। आज के विद्यार्थी के सम्मुख देश में एकता की भावना उत्पन्न करने एवं नए समाज के निर्माण की चुनौतियां भी हैं। देश में आतंकवाद उभर रहा है। उन्हें खत्म करने का काम आज का छात्र वर्ग ही कर सकता है। आज के छात्र के सामने देश के नव-निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी चुनौती है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यह वर्ग देश को प्रगति की राह में आगे ले जाने के दायित्व का निर्वाह करेगा। उससे ऐसी अपेक्षा करना अनुचित है, पर असंतुष्ट विद्यार्थी भला देश के उत्थान का काम क्या रुचिपूर्वक कर सकेगा। उसके असंतोष के कारणों को जानकर उनका निदान करना आवश्यक है।

अनु मिश्रा, सीवान

मगध महिला कॉलेज पटना में छात्र-छात्राओं ने सरस्वती पूजा के अवसर पर बसंत उत्सव मनाया

संविधान की मर्यादा का रखें ख्याल

महात्मा गांधी ने गणतंत्र के लिए यह विचार रखा था कि वह ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करेंगे जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी यह अहसास हो यह देश उसका है। इसके निर्माण में उनका योगदान है। उसकी आवाज का यहां महत्त्व है। लेकिन वर्तमान में शायद राजनेता इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं जिससे आज गण और तंत्र के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। गण पर तंत्र का हावी होना यह भी दर्शाता है कि देश की राजनीति और नौकरशाही में असामाजिक तत्त्वों की बढ़ोतरी हो रही है। गण के तंत्र में आए खोट को दूर करने के लिए गण भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक तौर पर जागरूक होकर दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। गणतंत्र की आन, बान और शान के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने अंदर देशभक्ति की भावना भरनी चाहिए। संविधान में मिले अधिकारों के प्रति ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी गंभीरता दिखानी होगी। अगर भारत को हर समस्या से मुक्त करना है तो देश के हरेक नागरिक को अपने स्वार्थ की भावना को छोड़ना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

दिसंबर तिमाही में सोने की मांग घटी

अगर बजट में खपत बढ़ाने के उपायों की घोषणा हुई तो सोने की मांग में आ सकता है सुधार

राजेश भयानी और पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 30 जनवरी

दिसंबर तिमाही में भारत में सोने की मांग एक साल पहले की तुलना में 18 प्रतिशत घटकर 194.3 टन रह गई जो इस अवधि में आठ वर्ष का निचला स्तर है। यह तिमाही बेहद महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें दीवाली का पर्व भी आता है। लेकिन ऊंची कीमत, कमजोर उपभोक्ता रुझान और ग्रामीण आय पर दबाव की वजह से सोने की मांग में सुधार नहीं दिखा।

वर्ष 2019 में भारत की कुल स्वर्ण मांग 9 प्रतिशत तक घटकर 690.4 टन रही। 2019 में भारत का शुद्ध स्वर्ण आयात 14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 646.8 टन रहा, लेकिन दिसंबर तिमाही के संदर्भ में आयात 18 प्रतिशत घटकर 138.5 टन दर्ज किया गया। यह खुलासा विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने आज जारी अपनी 2019 की स्वर्ण मांग रुझान रिपोर्ट में किया है। हालांकि डब्ल्यूजीसी को 2020 में देश में सोने की मांग में सुधार आने की संभावना है। डब्ल्यूजीसी के प्रबंध निदेशक (भारत) सोमसुंदरम पीआर का कहना कि 2020 में भारत की स्वर्ण मांग 700-800 टन रहने की संभावना है, जो पिछले साल 690.4 टन थी।

उनका कहना है कि हालांकि पिछले 10 वर्षों में भारत में सोने की औसत मांग 843 टन रही है और सराफा कारोबार में पारदर्शिता लाने के सरकारी प्रयासों से यह मांग इस स्तर से नीचे बने रहने की संभावना है।

वैश्विक रूप से सोने की मांग के रुझानों पर नजर रखने वाली अन्य एजेंसी जीएफएमएस का कहना है कि अनधिकृत सोने से भारत में मांग परिदृश्य में नकारात्मक बदलाव आया है। सोमसुंदरम के अनुसार, '2019 में देश में लगभग 115-120 टन सोने की तस्करी हुई थी जो पूर्ववर्ती वर्ष के 90-95 टन से अधिक है।'

पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया जिससे देश में इस धातु की तस्करी को बढ़ावा मिला।

कैलेंडर वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में दुनिया के दो सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ताओं भारत और चीन का वैश्विक मांग में आई गिरावट में 80 प्रतिशत का योगदान रहा। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी और कमजोर आर्थिक हालात की वजह से इस धातु की मांग पर दबाव देखा गया।

चौथी तिमाही में चीन की आभूषण मांग सालाना आधार पर 10 प्रतिशत घटकर 159.7 टन रही, जबकि पूरे वर्ष 2019 में मांग 7 प्रतिशत घटकर 637.3 टन रही। डब्ल्यूजीसी के अनुसार सुस्त अर्थव्यवस्था, बढ़ती मुद्रास्फीति, वैश्विक व्यापारिक तनाव, सोने की ऊंची कीमतों और युवा पीढ़ी द्वारा हल्के आभूषणों पर ध्यान दिए जाने से 2019 में मांग पर दबाव बढ़ गया। दूसरी तरफ, भारत में चौथी तिमाही में स्वर्ण आभूषण मांग सालाना आधार पर 17 प्रतिशत घटकर 149 टन रह गई।

डब्ल्यूजीसी का मानना है कि सोने के लिए चौथी तिमाही में मांग 1,045.2 टन रही, जो सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की गिरावट है। आभूषण मांग सालाना 10 प्रतिशत गिरकर 2011 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। सालाना आधार पर (2019 में), सोने की मांग 1 प्रतिशत घटकर 4355.7 टन रह गई, क्योंकि स्वर्ण बिस्कुट और सिक्के, आभूषण की कमजोर मांग से उपभोक्ता धारणा प्रभावित हुई।

सोने की वैश्विक मांग (टन में)

	2018	2019	तिमाही*
सोने की मांग	4,401	4,356	1,045
आभूषण	2,240	2,107	584
तकनीक	335	327	84
खुदरा निवेश	1,094	871	241
ईटीएफ	76	401	27
केंद्रीय बैंक	656	650	110
भारत की मांग/आपूर्ति			
कुल सराफा आयात	756	647	139
रिसाइकल सोना	87	120	29
घरेलू आपूर्ति	11	11	3
कुल आपूर्ति	853	777	170
कुल ग्राहक मांग	760	690	194

* अक्टूबर-दिसंबर 2019, स्रोत- मेटल फोकस, डब्ल्यूजीसी

सोने में आ सकती है तेजी

- सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी
- जुलाई में शुल्क वृद्धि के बाद सोने की तस्करी बढ़ी है
- इस साल सोने की कीमतें 1700 डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं

कपड़ा क्षेत्र के लिए ड्रॉबैक में संशोधन

निर्यातक चाहते हैं और राहत

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 30 जनवरी

वित्त मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र के लिए ड्रॉबैक अनुसूची में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह फरवरी से प्रभावी होगी। सूती उत्पादों के लिए यह ड्रॉबैक करीब 0.2 प्रतिशत होगा, जबकि मानव-निर्मित फाइबर और मिश्रित धागे वाले कपड़ों के लिए यह तकरीबन 0.4 से 0.6 प्रतिशत रहेगा। हालांकि इस घोषणा का स्वागत करते हुए निर्यातकों ने कहा कि सरकार को एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) पर हस्ताक्षर तथा राज्य व केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) में छूट के निपटारे पर ध्यान देना चाहिए जिससे निर्यातकों की कार्यशील पूंजी प्रभावित हो रही है।

यह अधिसूचना 4 फरवरी, 2020 से प्रभावी होगी। संशोधन के बाद सूती टी-शर्ट के लिए ड्रॉबैक दर मौजूदा 1.9 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत हो जाएगी। मिश्रित धागे से बने कपड़े के लिए मौजूदा 2.9 प्रतिशत की तुलना में यह दर 3.5 प्रतिशत और मानव-निर्मित धागे वाले कपड़े के लिए मौजूदा 2.5 प्रतिशत की तुलना में यह दर तीन प्रतिशत होगी।

निर्यातकों ने कहा कि यह इजाफा मामूली है और इस बात को लेकर संशय है कि इससे निर्यात में वृद्धि होगी। वर्ष 2018-19 में (अप्रैल से दिसंबर) सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात 11.363 अरब डॉलर था और वर्ष 2019-2020 में यह बढ़कर 11.457 अरब डॉलर हो गया।

तिरुपुर से 24,000 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात करने वाले निर्यातकों के बड़े वर्ग का प्रतिनिधि करने वाले संगठन तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि निर्यातक ने केवल ज्यादा दर चाहते हैं, बल्कि वे मुक्त व्यापार समझौते भी चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखने का फैसला किया है।

एक प्रमुख निर्यातक ने कहा कि संबंधित कर सहित जिस भी शुल्क और कर का भुगतान किया जाता है, वह जीएसटी, आरओएससीटीएल और ड्रॉबैक के रूप में वापस दिया जाता है। सरकार इससे ज्यादा नहीं देगी। वे केवल यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ एफटीए में शामिल हो सकते हैं।

चिंता की एक अन्य बात यह है कि सरकार ने लंबित दावों का निपटारा नहीं किया है। उदाहरण के लिए, अकेले तिरुपुर की इकाइयों के लिए ही करीब 1,400 करोड़ रुपये लंबित हैं और सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही आरओएससीटीएल लाभ के दावे की प्रक्रिया शुरू की है।

वस्त्रों की कीमत

वस्त्र	पहले*	बाद में*
टी शर्ट		
कपास	1.9	2.1
मिश्रित	2.9	3.5
मानव निर्मित	2.5	3
बच्चों के कपड़े		
कपास	1.9	2.1
मिश्रित	2.1	2.5
मानव निर्मित	2.4	2.9
पजामा		
कपास	2.2	2.4
मिश्रित	2.3	2.6
मानव निर्मित	2.4	2.9

* संशोधन प्रतिशत में

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 30	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,732.5	-0.8	2,014.3	5.0
Copper	5,698.0	-3.1	6,252.6	2.1
Nickel	12,630.0	-25.3	13,358.5	-23.6
Lead	1,886.0	-16.4	2,154.1	-0.2
Tin	16,325.0	-2.8	17,275.1	-3.6
Zinc	2,256.0	-12.0	2,531.8	-6.0
Gold ($/ounce)	1,581.3*	5.7	1,770.0	5.3
Silver ($/ounce)	17.8*	-0.6	20.1	-1.0
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	57.3*	-4.6	59.0	-3.5
Natural Gas ($/mmBtu)	1.9*	-31.2	1.9	-31.2
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	197.3	9.4	290.3	-4.3
Maize	186.6*	2.5	273.2	-2.7
Sugar	410.6*	20.6	486.6	-1.7
Palm oil	712.5	22.3	1,159.8	26.3
Rubber	1,456.0*	3.4	1,902.4	8.8
Coffee Robusta	1,291.0*	2.3	1,769.5	-7.4
Cotton	1,536.4	6.1	1,581.5	-2.5

* As on Jan 30, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.5& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	25.8	35224
Oil and Oilseeds	309.0	85648
Spices	0.4	9
Metal(Jan 29)		
Metal- non ferrous	5523.0	42463
Metal- precious	12951.9	444
Oil and gas(Jan 29)		
Gas	1923.7	52138
Oil	15778.9	2372

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	242.9	137879
Grains	137.2	95145
Oil and Oilseeds	591.4	463340
Others	130.0	66670
Pulses	56.5	35285
Spices	41.4	22815

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Aluminium (May 29)	142.0	1.3
Gold Petal (Jan 31)	4049.0	1.1
Gold Mini (Feb 05)	40321.0	0.3
Aluminium Mini (Jan 31)	148.0	0.3
Gold (Feb 05)	40350.0	0.3
Silver (Mar 05)	45551.0	0.2
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Feb 25)	134.6	-2.0
Cardamom (Feb 14)	3912.6	-1.4
Crude Palm Oil (Jan 31)	775.7	-1.2
Copper (Jan 31)	433.2	-1.0
Cotton (Jan 31)	19220.0	-1.0
Kapas (Apr 30)	1085.0	-1.0

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Soyabean Indore (Feb 20)	4086.0	0.5
Losers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1793.0	-2.6
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	7029.0	-1.2
Guar Seed 10 (Feb 20)	3950.0	-1.2
Jeera Unjha (Mar 20)	14035.0	-1.2
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4141.0	-1.2
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3940.0	-1.1
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1086.0	-1.0
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6010.0	-0.9
Chana-Bikaner (Mar 20)	3997.0	-0.9
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	856.4	-0.6
Coriander-Kota (Apr 20)	6510.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Alumini-Mumbai (Jan 31)	148.0	3.4
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	3.4
Copper Mum (Jan 31)	433.2	1.8
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3912.6	1.7
Zinc Mumbai (May 29)	181.6	1.4
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19220.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1197.7	-11.1
Lead Min Mumbai (Jan 31)	146.2	-4.3
Nickel Mumbai (Jan 31)	940.0	-1.3
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	177.0	-1.2
Silver Ahm (Mar 05)	45551.0	-1.2
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	45569.0	-1.2

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Delhi (Feb 20)	1893.0	2.3
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	755.3	1.4
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3211.0	1.1
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1893.0	0.6
Maize-Sangli (Feb 20)	1953.0	0.5
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6010.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1731.0	-19.5
Jeera Unjha (Mar 20)	14035.0	-7.9
Coriander-Kota (Apr 20)	6510.0	-2.6
Soy Bean Indore (Feb 20)	4086.0	-2.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	7029.0	-1.8

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals .....Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg 106.....(108)
Aluminium ingots /kg 144.....(144)
Brass sheet cutting /kg 325.....(325)
Brass utensil scraps/kg 300.....(305)
Copper heavy scrap /kg 415.....(418)
Copper utensil scraps/kg 394.....(391)
Copper wire bar /kg 447.....(448)
Lead ingots /kg 154.....(154)
Nickel Cathodes /kg 955.....(960)
Tin slabs /kg 1235.....(1235)
Zinc slabs /kg 181.....(181)
Source:Bombay Metal Exchange

Cotton .....Mumbai
Bengal Deshi /Qtl 10236.....(10236)
DCH - 32 /Qtl 11389.....(11360)
Jaydhar /Qtl 9758.....(9758)
Shankar- 6 /Qtl 11164.....(11135)
Source:Cotton Association of India

Oil .....Mumbai
Castor FSG /10kg 865.....(863)
Castor Comm /10kg 855.....(853)
Ricebran oil/10kg 820.....(820)
Groundnut oil /10kg 1140.....(1140)
Linseed oil /10kg 935.....(935)
Karanji /10kg 800.....(800)
Palm oil /10kg 840.....(840)
Sunflower exp ref /10kg 880.....(875)
Sunflower oil exp /10kg 855.....(850)
Soyabean ref / 10kg 870.....(865)
Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar .....Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl 3372-3585 .....(3362-3585)
Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel .....
NYSE Crude 52.06.....(53.33)
Brent Crude (UK) 57.38 .....(58.79)
Brent Crude (WTI) 53.33.....(53.33)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu 1.84.....(1.87)
Furnace/ 180 Cst &/bbl 302.69.....(317.33)
Naptha spot /Rs/MT 45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T. 36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L. 33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold .....Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms 40684.....(40302)
Pure (99.90 Purity) /10 gms 40848.....(40464)
Silver.999/ kg 46170.....(45535)
Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19019.05	19068.85
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.95	143.05
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1830.00	1850.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1886.25	1881.65
Barley Jaipur (N)	1 Q	2150.00	2150.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3850.00	3850.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4090.00	4090.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4055.00	4030.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4125.00	4088.75
Chana Delhi (N)	1 Q	4350.00	4314.60
Chana-Akola (N)	X	4087.50	4000.00
Coriander-Gondal (N)	X	6444.00	6400.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6587.50	6562.50
Coriander-Kota (N)	1 Q	6686.25	6686.25
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1936.20	1928.40
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1967.90	1958.35
Cotton-Kadi (N)	1 B	19050.90	19027.00
CPO-Kandla (M)	10 K	781.20	768.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	755.00	745.15
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	770.00	750.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	906.20	907.65
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1547.10	1553.40
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3448.90	3462.95
Gold Ahm (M)	10 G	40312.00	40717.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32379.00	32705
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4041.00	4081.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7200.00	7158.35
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3965.90	3941.65
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3940.00	3950.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1107.40	1095.95
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	103.35	103.35
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	15900.00	15600.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15233.35	15233.35
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	870.00	863.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1032.45	1029.30
Kapas-Rajkot (N)	X	1035.20	1035.25
Lead Mum (M)	1 K	156.70	152.75
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1940.00	1900.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2260.00	2228.15
Maize-Erode (N)	X	1931.80	1920.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2260.00	2228.15
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2030.00	2015.00
Maize-Sangli (N)	X	1945.85	1942.70
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4725.00	4725.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7756.25	7768.75
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4385.50	4385.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	957.20	952.50
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3175.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3216.00	3213.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	335.40	333.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33854.55	33669.25
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	852.50	850.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	750.00	750.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1912.50	1916.65
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5318.35	5318.35
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	840.00	829.15
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	881.05	876.55
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	881.15	876.60
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	887.50	887.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13600.00	13600.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13592.00	13583.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	45478.00	46116.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4186.00	4182.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4095.25	4095.25
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4216.75	4242.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4201.00	4141.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33500.00	33311.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	881.60	877.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31830.00	32020.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32090.00	32230.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28950.00	29060.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3252.50	3225.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3372.35	3390.50
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3281.00	3289.55
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3461.90	3476.20
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3301.50	3290.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3140.00	3150.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6000.00	5985.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2208.00	2210.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2170.50	2170.50
Wheat New Indore (N)	1 Q	2192.50	2187.50
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2115.00	2115.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2212.50	2203.35
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5650.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5712.50	5700.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	181.05	179.15

* as on Jan 29, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

बुलियन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के सामने प्रबंधन और सुरक्षा।
एमसीएक्स पर हेज करें।
MCX METAL & ENERGY Trade with Trust
www.mcxindia.com

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (गुरुवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19220, 19280, 19180, 19220	145	19	2577
Feb 28	19460, 19530, 19440, 19500	1743	271	27139
Mar 31	19760, 19820, 19730, 19780	196	36	4605
Apr 30	20060, 20060, 20060, 20060	04	1	208
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1841, 1852, 1785, 1793	77010	4815	62630
Mar 20	1862, 1875, 1811, 1816	37410	2513	53730
Apr 20	1892, 1904, 1838, 1845	5200	435	14080
May 20	1922, 1935, 1874, 1886	1040	81	3810
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1091, 1091, 1084, 1085	340	63	688
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1092, 1092, 1084, 1086	1033	600	3629
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3996, 4000, 3936, 3950	20895	2166	63100
Mar 20	4038, 4044, 3984, 3998	13375	1254	27890
Apr 20	4074, 4080, 4030, 4062	180	31	235
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3980, 4000, 3920, 3940	4055	511	16985
Mar 20	3996, 4018, 3934, 3958	2875	378	14340
Apr 20	4038, 4038, 3958, 4006	200	26	3450
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	778.6, 782.5, 775.5, 775.7	3800	215	14350
Feb 28	757.6, 759.5, 745.3, 750.8	24420	1812	50470
Mar 31	751.1, 754, 738, 744.2	8380	613	18940
Apr 30	739.7, 742.5, 735.5, 741.5	2160	154	1650
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1207.2, 1214, 1200.5, 1201.4	148.68	358	216.72
Apr 20	4024, 4058, 4020, 4052	5655	796	63740
May 20	4040, 4050, 4022, 4048	710	111	13210
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7090, 7129, 6990, 7029	10255	1143	27895
Mar 20	7185, 7210, 7080, 7118	7950	791	38545
Apr 20	7260, 7274, 7200, 7229	120	22	230
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4031, 4044, 3982, 3997	10210	815	23800
Apr 20	4027, 4027, 3974, 3985	3440	302	9020
May 20	4062, 4062, 4005, 4025	450	45	2400
Jun 19	4045, 4045, 4045, 4045	10	1	20
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3913.2, 3913.2, 3912, 3912.6	0.2	2	5.1
Mar 13	3912, 3934, 3851, 3909.6	0.9	8	3.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6570, 6570, 6443, 6510	1950	177	9220
May 20	6480, 6540, 6440, 6490	90	8	460
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	14170, 14200, 14005, 14035	408	134	2262
Apr 20	13880, 13945, 13710, 13730	471	140	1473
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6080, 6098, 5972, 6010	1775	330	5045
Apr 20	5942, 6000, 5900, 5944	885	162	4230
May 20	5970, 5970, 5970, 5970	5	1	125
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	140.5, 140.5, 140.5, 140.5	2	2	3
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	147.95, 147.95, 144.15, 144.5	86	47	416
Feb 28	139.35, 139.8, 139, 139.6	3024	2083	4474
Mar 31	140.15, 140.25, 139.65, 140	50	49	216
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	429.2, 433.35, 429.2, 431.85	7.5	3	355
Feb 28	428.75, 429.35, 425.9, 428.25	17422.5	5922	13415
Mar 31	431.6, 431.6, 427.85, 430.4	345	126	622.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	146.75, 147.4, 145.6, 146.55	7209	4800	6379
Mar 31	147.45, 148.1, 146.75, 147.55	132	108	210
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	948.4, 948.4, 948.4, 948.4	1.5	1	103.5
Feb 28	936, 942.7, 931.5, 938.8	12966	7796	4015.5
Mar 31	931.3, 937.9, 931.3, 936.5	58.5	39	96
Zinc MCX(1 K)				
May 29	178.85, 180.6, 178.85, 179.7	3	3	21
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	175.6, 175.6, 175.1, 175.5	104	19	1084
Feb 28	177.4, 177.45, 175.35, 176.25	20384	12186	17432
Mar 31	177.7, 177.85, 175.9, 176.4	1147	854	1195
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40486, 40774, 40472, 40728	3.77	3148	2.07
Apr 03	40741, 40933, 40728, 40860	5.77	4897	19.17
Jun 05	40800, 40992, 40800, 40905	0.66	520	3.82
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	32328, 32364, 32328, 32357	0	9	0
Feb 28	32300, 32387, 32252, 32319	0	311	0.01
Mar 31	32290, 32340, 32232, 32321	0	27	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40400, 40674, 40400, 40643	0.27	2099	0.22
Mar 05	40470, 40745, 40470, 40676	0.77	6238	0.81
Apr 03	40656, 40890, 40656, 40812	0.12	889	0.21
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Jan 31	4029, 4069, 3969, 4058	0	36	0
Feb 28	4012, 4024, 4012, 4022	0	1013	0.01
Mar 31	4020, 4038, 4020, 4036	0	194	0
Apr 30	4030, 4031, 4030, 4031	0	2	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45740, 46300, 45740, 46247	313.35	8554	281.25
May 05	46388, 46819, 46360, 46756	3.9	123	22.53
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45690, 46332, 45690, 46264	37.9	26130	28.64
Apr 30	46198, 46825, 46198, 46788	4	2839	5.71
Jun 30	46900, 47200, 46720, 47166	0.02	21

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप से दुनिया के बाजार और कारोबार पर असर पड़ने की आशंका

वायरस से वैश्विक बाजार में कंपकंपी

साल के सबसे ऊंचे स्तर से 2 से 9 फीसदी तक लुढ़के बाजार, ब्रोकरेज ने सार्स से ज्यादा असर की जताई आशंका

जश कृपलानी

चित्रांकन: अजय मोहंती

अमेरिका और चीन के बीच समझौता होने की खबरों से वैश्विक बाजारों में जितनी बढ़त आई थी, वह अब कोरोनावायरस की वजह से खत्म होती जा रही है। दो प्रमुख वैश्विक सूचकांक मध्य जनवरी के अपने सर्वोच्च स्तरों से 2-9 फीसदी नीचे आ गए हैं। वैश्विक बाजारों का मूल्यांकन जनवरी के आखिरी सप्ताह में 2.2 लाख करोड़ रुपये कम हुआ है।

विदेशी ब्रोकरेज वैश्विक बाजारों पर कोरोनावायरस का सार्स से भी अधिक असर पड़ने की आशंका जता रही हैं। वर्ष 2003 में सार्स वायरस भी चीन में भी पैदा हुआ था। क्रेडिट सुइस ने एक नोट में कहा, 'हमारा अनुमान है कि एशिया पर बड़ा और संभवतया दीर्घकालिक वृहद आर्थिक असर पड़ेगा, जो सार्स से पड़े असर से भी अधिक होगा। हमारा मानना है कि अब से 12 महीने बाद एशियाई अर्थव्यवस्था वहीं होगी, जहां वह वुहान वायरस नहीं फैलने पर होती। लेकिन हमें इसके नतीजे अत्यंत खराब आने के जोखिम नजर आ रहे हैं।'

दिसंबर के मध्य में अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी समझौते के पहले चरण की घोषणा के बाद इस वायरस के फैलने की खबरें आने तक वैश्विक बाजारों में भारी तेजी आई थी। इस तेजी की बदौलत कुछ प्रमुख वैश्विक सूचकांक अपने अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर पहुंच गए थे। डाऊ जोंस, नैस्डैक, एसऐंडपी 500, निफ्टी, सेंसेक्स, ब्राजील का इबोवेस्पा और जर्मनी का डैक्स सूचकांक ने जनवरी में नई ऊंचाई हासिल की थी।

ब्रोकरेज इस बात से चिंतित हैं कि वायरस का प्रकोप लंबे समय तक बना रह सकता है। क्रेडिट सुइस के विश्लेषकों ने कहा, 'सार्स को लेकर उपभोक्ता और पर्यटन क्षेत्र में केवल एक तिमाही में खौफ रहा था, लेकिन वुहान वायरस लंबे समय तक रुझान को प्रभावित कर सकता है। अगर वायरस के जीन में बदलाव से स्पेन के फ्लू जैसा दूसरा दौर शुरू होता है तो रुझान पर असर लंबे समय तक बना रह सकता है।' अब तक एशियाई सूचकांक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। हैंग सेंग जनवरी के मध्य में अपने सर्वोच्च स्तर से 9 फीसदी लुढ़क चुका है। इस तरह यह अमेरिका-चीन के कारोबारी समझौते की बदौलत हुई 11.5 फीसदी बढ़ोतरी में से ज्यादातर गंवा चुका है।

- वैश्विक बाजारों का मूल्यांकन जनवरी के आखिरी हफ्ते में घटा
- अमेरिका-चीन के बीच कारोबारी समझौते से चढ़े थे वैश्विक बाजार
- भारत पर वायरस का कम असर पड़ने की दिख रही संभावना

अन्य एशियाई सूचकांकों में ताइवान ताइएक्स इस साल के सबसे ऊंचे स्तर से 6.2 फीसदी लुढ़क चुका है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.26 फीसदी लुढ़का है। वहीं चीन का शांघाई कंपोजिट 4.46 फीसदी नीचे आया है। घरेलू सूचकांक- निफ्टी और सेंसेक्स क्रमश: 2.6 फीसदी और 2.5 फीसदी लुढ़के हैं।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत उन एशियाई देशों में से एक हो सकता है, जिन पर कोरोनावायरस का कम असर पड़ेगा क्योंकि उसका चीन के साथ संपर्क कम है। हालांकि वे आगाह करते हैं कि अफसरशाही के ढांचे की वजह से सरकार की बीमारी के फैलाव को रोकने की क्षमता प्रभावित होगी।

विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकोप का व्यापक वैश्विक असर होगा क्योंकि वैश्विक कारोबार से चीन के संपर्क में अहम बढ़ोतरी हुई है। मैक्वायरी ने एक नोट में कहा, 'एक बार फिर असर एशियाई उपभोग पर पड़ने के आसार हैं। यात्रा कारोबार पर सबसे ज्यादा असर होगा। चीन की अर्थव्यवस्था की अहमियत बढ़ी है, इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर दिखेगा।'

दूसरे देशों ने बढ़ाई जांच कंपनियों ने की बंदी

चीन के शहर वुहान से निकाले गए विभिन्न देशों के सैंकड़ों नागरिकों को उनके देशों ने निगरानी के लिए अलग रखकर गुरुवार को उनकी जांच शुरू कर दी है। कोरोनावायरस के संक्रमण से फैली महामारी में अब तक 170 लोग मारे गए हैं। इस वायरस का असर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ने की चिंताओं की वजह से वैश्विक बाजारों में भी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। कोरोनावायरस के संक्रमण से मरने वालों की तादाद बढ़ने और संक्रमण के और अधिक मामले की पुष्टि के साथ ही एशियाई क्षेत्रों के शेयरों और मुद्रा में गिरावट की स्थिति देखी जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था को लग रहे झटके का असर अगले कुछ महीने में दुनिया में भी नजर आएगा।

दक्षिण कोरिया में रोष और भय की वजह से विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी है जबकि हॉन्गकॉन्ग में भी हड़ताल का खतरा मंडराने लगा है। गूगल और स्वीडन की आइकिया ने अन्य बड़ी कंपनियों की तरह ही चीन में परिचालन बंद करने का फैसला किया। चीन की फैक्टरियों में हजारों की तादाद में काम करने वाले कामगार नववर्ष की छुट्टियां खत्म होने के बाद अगले हफ्ते भी काम पर लौट पाएंगे या नहीं इसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड ने कहा कि उसने चीन की फैक्ट्रियों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं।

कोरोनावायरस से होने वाली ज्यादातर मौत हुबेई प्रांत में हुई है जहां करीब 6 करोड़ लोग रहते हैं। वायरस का संक्रमण कम से कम अन्य 16 देशों में भी फैला है जहां 105 मामले की पुष्टि हो चुकी है लेकिन चीन के बाहर किसी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।

ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश अगले दो हफ्ते में अपने नागरिकों को वापस बुला लेंगे। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि विमान से 300 यात्री लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विमान को लेकर चीन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। न्यूजीलैंड के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले यात्रियों के लिए अगले दो हफ्तों तक अलग रखने की व्यवस्था की जा रही है।

सिंगापुर ने कहा कि वह अपने 92 नागरिकों को वुहान से वापस लाएगा और इनके साथ विदेश मंत्रालय के कर्मचारी भी होंगे। इन्हें पहले किसी अस्पताल या फिर 14 दिनों के लिए अलग रखा जाएगा। दक्षिण कोरिया में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संक्रमित लोगों को रखने के लिए तय की गई अलग जगह आवासीय इलाके से दूर होनी चाहिए। इन प्रदर्शनकारियों ने एक मंत्री पर गुस्से में अंडे फेंके।

...हालात गंभीर

- सैंकड़ों विदेशियों को चीन से निकाला गया
- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने शांति की अपील की
- वायरस संक्रमण बढ़ने से शेयर बाजार में गिरावट

राशि आवंटित

चीन ने खतरनाक कोरोनावायरस को रोकने के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए गुरुवार को करीब चार अरब डॉलर की राशि आवंटित की, वहीं जैक मा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के संगठन भी मदद कर रहे हैं। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में दिसंबर में कोरोनावायरस का संक्रमण शुरू हुआ और अब पूरे देश में इसके मामले देखे जा रहे हैं।

चीन के अधिकारी इस आपदा को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने गुरुवार को बताया कि 38 और लोगों के जान गंवाने के बाद देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 170 हो गई है, वहीं संक्रमण के कुल 7711 मामलों की पुष्टि हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि चीन ने कोरोनावायरस के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई छेड़ने के लिए 27.3 अरब युआन (करीब 3.94 अरब डॉलर) की राशि आवंटित की है। चीन ने वायरस के कारण बाधित कृषि आपूर्ति के चलते खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसानों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है।

वहीं रूस ने कहा कि वह कोरोनावायरस के खतरे के मद्देनजर चीन के साथ लगने वाली अपनी सीमा बंद कर रहा है। वहीं इजराइल की राष्ट्रीय विमानन कंपनी इल आल ने घोषणा की कि वह पेइचिंग जाने वाली उड़ानें निलंबित कर रही है। *रॉयटर्स*

प्रकोप बढ़ा तो कच्चे तेल की वैश्विक मांग भी घटेगी

पुनीत वाधवा

अगर कोरोना वायरस और फैलता है तो कच्चे तेल की वैश्विक मांग फरवरी, 2020 में सालाना आधार पर 42 फीसदी घटकर 7.7 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ सकती है, जो इस समय 13.3 लाख बैरल प्रतिदिन है। एसऐंडपी ग्लोबल प्लैट्स के एक नोट में यह कहा गया है।

एसऐंडपी ग्लोबल प्लैट्स ने कहा, 'वायरस का प्रकोप अत्यधिक गंभीर होने पर वैश्विक मांग में वृद्धि मई तक नकारात्मक रहेगी। वहीं स्थिति बेहतर होने पर यह मार्च में धनात्मक हो जाएगी।' कोरोना वायरस वित्तीय बाजारों को पहले ही हिला चुका है। बीते दौर में वायरस फैलने के अनुभव इस ओर इशारा करते हैं कि बाजार जल्द ही वापसी कर लेते हैं। रोबोबैंक इंटरनैशनल के विश्लेषकों के मुताबिक चीन पर वास्तविक असर वहां की सरकार की वायरस को नियंत्रित करने की क्षमता और असर को कम करने के लिए नीतिगत पहलों पर निर्भर करता है।

वायरस के फैलने के कारण ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, स्विस इंटरनैशनल एयरलाइंस और ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस समेत सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियां पहले ही अपनी उड़ान स्थगित या कम कर चुकी हैं। अब तक इस वायरस की चपेट में दुनियाभर के 6,100 से अधिक लोग आ चुके हैं। भारत, अमेरिका और यूरोप में नए मामले सामने आ रहे हैं। चीन में मरने वाले लोगों का आकड़ा भी बढ़ा है।

प्लैट्स एनालिटिक्स के प्रमुख (मांग, रिफाइनिंग और कृषि विश्लेषण) क्लोडियो गलीमबेरटी का मानना है कि वायरस का फैलाव अत्यंत गंभीर शक्ल लेने पर चीन की परिवहन प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होगी। फरवरी में चीन की 23 फीसदी यात्राओं और मालभाड़ा दौरों को रद्द किया जा रहा है। इसका यह भी मानना है कि चीन में इस अवधि में विमानन उद्योग की मांग में अप्रत्याशित 50 फीसदी कमी आएगी।

विश्लेषकों ने कहा कि कोरोना वायरस ऐसे समय फैला है, जब तेल आपूर्ति के लिए भूराजनीतिक जोखिम 2020 में अधिक रहने के आसार हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान एक-दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को नवंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक प्रतिबंध में राहत नहीं मिलने के आसार हैं। हालांकि अमेरिका की प्रतिबंधों की नीति के बारे में कोई अनुमान लगाना मुश्किल है।

तेल की वैश्विक मांग फरवरी में घटेगी

रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) 5-6 मार्च को होने वाली अपनी बैठक को जल्द करने पर चर्चा कर रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप से तेल बाजारों पर लगातार चोट पड़ रही है।

ओपेक उत्पादन में बड़ी कटौती करने या आपूर्ति पर मौजूदा प्रतिबंधों के मार्च में खत्म होने के बाद भी उन्हें जारी रखने के बारे में विचार कर रहा है। इन घटनाक्रमों को मद्देनजर रखते हुए विश्लेषक पहले ही चीन में फरवरी और मार्च में रिफाइनरी उत्पादन अनुमान 6 से 10 लाख बैरल प्रतिदिन घटा दिया है। चीन में कच्चे तेल का आयात अप्रैल और मई में और सुस्त पड़ने के आसार हैं। फ्रैंकलिन टेंपलटन इमर्जिंग मार्केट्स रिसर्च के विश्लेषकों ने हाल में एक नोट में लिखा, 'वर्ष 2003 में सार्स के समय की तुलना में इस समय अर्थव्यवस्था में खपत की अहम भूमिका है। इसका चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 70 फीसदी से अधिक हिस्सा है, जो 2003 में 40 फीसदी से कम था। इसके चलते हमारा यह मानना है कि इस बार अर्थव्यवस्था पर असर वर्ष 2003 की तुलना में अधिक होगा। हालांकि सुधार उतना तेज नहीं रहने के आसार हैं क्योंकि अब चीन की अर्थव्यवस्था न केवल बड़ी है बल्कि सुस्त रफ्तार से भी बढ़ रही है, जबकि 14 साल पहले अर्थव्यवस्था दो अंकों में बढ़ रही थी।'

केरल में पहले मामले की पुष्टि

टीई नरसिम्हन

देश में कोरोनावायरस का पहला मामला केरल में सामने आया है। चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही एक छात्रा में कोरोनावायरस की पुष्टि हुई है और उसे अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है। पीआईबी की एक विज्ञप्ति के मुताबिक मरीज की हालत स्थिर है और उसके स्वास्थ्य पर करीबी नजर रखी जा रही है।

राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जोर दिया कि राज्य का स्वास्थ्य नेटवर्क आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है और एहतियात के तौर पर कई कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया में अफवाह न फैले इसका ख्याल रखना चाहिए।

वहीं केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने वुहान से लौटे चार लोगों में से एक लड़की में कोरोनावायरस की पुष्टि की है। संक्रमित छात्रा को त्रिशूर के जनरल हॉस्पिटल में अलग वार्ड में निगरानी में रखा गया है।

शैलजा ने कहा कि केरल से कुल 20 नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है जिनमें से 10 के नमूने निगेटिव पाए गए हैं। अन्य छह नमूने लंबित हैं और शुरुआती परीक्षण में एक कोरोनावायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया है। सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल में अलग वार्ड बनाया है और संदिग्ध मरीजों को वहां रखा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में भी अनिश्चितता

अर्णव दत्ता और शुभायन चक्रवर्ती

चीन में कोरोनावायरस से पैदा हुई ताजा महामारी यदि फरवरी के दूसरे पखवाड़े तक बनी रहती है तो इससे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज निर्माताओं की आगामी व्यावसायिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

चूंकि बड़ी तादाद में कलपुर्जों का आयात पड़ोसी देश चीन से किया जाता है, इसलिए मोबाइल हैंडसेट, एयर कंडीशनर, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर के निर्माताओं को आने वाले महीनों में आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

चीनी अधिकारियों ने कई उत्पादों का निर्माण 9 फरवरी तक बंद करा दिया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे भी शामिल हैं। उद्योग संस्था आईसीईए के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने कहा, 'भारत में उसके सदस्यों के तौर पर सभी पंजीकृत सभी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक और हैंडसेट निर्माताओं को चेतावनी जारी की गई है। चीन में नव वर्ष से पहले स्वाभाविक रूप से किए जाने वाले माल के भंडारण से प्रभाव कम दिखा है। समस्या 10 फरवरी के बाद भी बनी रहती है तो इससे दबाव बढ़ेगा।'

सीईएएमए के अध्यक्ष एवं गोदरेज ऐंड बॉयस के कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी के अनुसार, कई कंपनियों के पास कलपुर्जों का स्टॉक उपलब्ध है जो फरवरी के अंत तक के लिए पर्याप्त साबित हो सकता है। नंदी ने कहा, 'लेकिन यदि चीन में स्थिति फरवरी के बाद भी खराब बनी रही तो भारत में निर्माण (अप्लायंसेज के लिए) पर प्रभाव पड़ेगा।'

एलसीडी और एलईडी टीवी के लिए फ्लैट पैनल, स्मार्टफोन के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और एसी तथा रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले कम्प्रेसर जैसे प्रमुख उत्पादों का आयात बड़े पैमाने पर चीन से किया जाता है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में चीन से 50,554 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों और एक्सेसरीज का आयात किया गया था, जिनमें से 33,600 करोड़ रुपये के हैंडसेट कलपुर्जे शामिल थे। अप्रैल से नवंबर 2019 तक की आठ महीने की अवधि के दौरान, दूरसंचार उपकरणों का कुल आयात 28,140 करोड़ रुपये का था।

अप्रैल से नवंबर के दौरान, जहां 4,200 करोड़ रुपये मूल्य के टीवी कलपुर्जों का आयात किया गया, वहीं पूरी तरह तैयार टीवी की आयात वैल्यू 1,750 करोड़ रुपये दर्ज की गई। एसी के कलपुर्जों (स्पिलिट मॉडलों के लिए इंडोर यूनिट) की आयात वैल्यू 1,820 करोड़ रुपये रही।

चीन से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात

करोड़ रुपये में	2018-19	2019-20 (अप्रैल-नवंबर)
दूरसंचार उपकरण, हैंडसेट आदि	50,554	28,140
टीवी और टीवी कलपुर्जे	8,780	5,880
एसी यूनिट एवं कलपुर्जे	3,990	1,820

स्रोतः वाणिज्य विभाग

वायरस के असर से बढ़ेगी खाद की आयात लागत

बीएस संवाददाता

कोरोनावायरस से फैली महामारी से वित्तीय बाजार में हलचल का माहौल है और अगर चीन में हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तथा इस महामारी पर निकट भविष्य में काबू नहीं किया जाता तब भारतीय निर्यातकों की चिंताएं बढ़ेंगी। चीन के साथ कारोबार पर कितना असर पड़ा है इसका अंदाजा 8 फरवरी के बाद ही लगेगा जब चीन के नववर्ष की छुट्टियां खत्म होंगी। हालांकि खाद, प्लास्टिक, रसायन के आयात पर असर पड़ सकता है क्योंकि वैश्विक स्तर पर चीन इनका बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

चीन से होने वाले शीर्ष 5 आयातित सामानों की सूची में खाद, जैविक रसायन और प्लास्टिक की वस्तुएं शामिल हैं। देश के गैर यूरिया या डीएपी उर्वरक के आयात पर असर पड़ सकता है। अगर चीन में हालात गंभीर होते हैं तब संयंत्रों के बंद होने से चीन का उत्पादन घटेगा और आखिरकार वैश्विक बाजार में चीन से आपूर्ति कम होगी। डीएपी उर्वरक की कीमतें पिछले एक-डेढ़ साल से ही कम हो रही हैं जो 425 डॉलर से घटकर अब 295 डॉलर प्रति टन हो गई हैं।

एक बड़ी विदेशी ब्रोकिंग कंपनी में खाद और रसायन विश्लेषक का कहना है कि जैविक रसायन और प्लास्टिककी वस्तुओं पर भी समान असर दिखेगा जिसका चीन बड़ा वैश्विक आपूर्तिकर्ता है। भारत 9 अरब डॉलर से ज्यादा रकम के खाद, रसायन और प्लास्टिक की वस्तुओं का आयात चीन करता है। हालांकि उनका कहना है कि जो घरेलू कंपनियां इन चीजों का उत्पादन करती हैं उन्हें इस वक्त फायदा होगा।

परिधान निर्यात

एक प्रमुख परिधान निर्यातक का कहना है कि वर्ष 2003 में जब चीन में सार्स वायरस फैला था तब 17 देशों में प्रसार के बावजूद ज्यादा असर नहीं पड़ा था और नई दवाइयों और टीके से इसे नियंत्रित कर लिया गया था। ऐसे में देश के निर्यात पर असर पड़ने का अंदाजा लगाना भी जल्दबाजी होगी। हालांकि परिधान उद्योग बटन, जिप, हुक, हैंगर आदि सामानों का आयात भी करता है।

डीएपी उर्वरक की कीमतें पिछले एक-डेढ़ साल से कम हो रही हैं

कपास निर्यात पर असर

भारत चीन में कपास का निर्यात भी करता है और पिछले साल चीन में 8-9 लाख गांठों का निर्यात किया गया था। इस साल भी कपास वर्ष (अक्टूबर-जनवरी) के पहले चार महीने में 6-7 लाख गांठें चीन भेजी गई हैं और चीन से 3-4 लाख गाठों के निर्यात का ऑर्डर भी मिला है। भारतीय कपास संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि अब तक कोई आपात स्थिति नहीं बनी है और निर्यात ऑर्डर फरवरी तक भेजे जाएंगे। इसके अलावा चीन में कॉफी निर्यात भी कम हो सकता है। कॉफी निर्यातक संगठन के अध्यक्ष रमेश राजा का कहना है कि वायरस संक्रमण की वजह से चीन में कॉफी की खपत पर असर होगा जिससे मांग में कमी आएगी। दो प्रमुख वैश्विक कॉफी खुदरा चेन ने अस्थायी रूप से अपने 2000 कॉफी शॉप बंद कर दिए हैं। भारत चीन में 33.6 करोड़ डॉलर कॉफी का निर्यात करता है जिनमें चाय और मसाले शामिल हैं।